

हम चलेंगे साथ साथ!

Вместе вперед! Together we shall move forward!



ISSN: 2713-1939 (PRINT) ISSN: 2713-1947 (ONLINE)

BRICS 20
RUSSIA 24

2024
ГОД СЕМЬИ





Фармацевтическая компания «ПанБио Фарм»

- **«ПанБио Фарм»** — поставщик препаратов в Россию для широкого круга направлений медицины: неврологии, ревматологии, гинекологии, фтизиатрии, пульмонологии, ортопедии и хирургии
- **Миссия компании PBF:** заботиться о мире в целом и здоровье каждого человека в отдельности. Делать добро и верить в успех.

- **Ведущая производственная площадка**
— Simpex Pharma Pvt. Ltd.

पंजीकरण संख्या

PINO FC 77&73489

ISSN: 2713-1939 (Print)

ISSN: 2713-1947 (Online)

प्रधान सम्पादक

डॉ० रामेश्वर सिंह

अतिथि सम्पादक

गौतम कश्यप

सम्पादकीय सलाहकार

प्रो० ल्यूदमिला ख़खलोवा

प्रो० बरीस वल्खोनस्की

प्रो० गुजेल स्ट्रिलकोवा

प्रो० इंदिरा गाजियेवा

डॉ० सोनू सैनी

श्री विनय शुक्ला

तकनीकी सलाहकार

नादेज़्दा सिंह

प्रकाशक का नाम एवं पता

NCO Russian Indian Friendship
Society "Disha" 117198 Moscow,
Street Ostrovityanova, 9/2-97

वेबसाइट : www.disha.su

दूरभाष : +7-985 341 38 59

ईमेल : disharusjournal@gmail.com

‘लेखों में व्यक्त विचारों से सम्पादक की
सहमति आवश्यक नहीं है।

निःशुल्क वितरण के लिए।

कुल प्रतियां : 900

अनुक्रमणिका

01. प्रधान सम्पादक की कलम से — डॉ० रामेश्वर जी	02
02. महामहिम राजदूत का सन्देश	03
03. अतिथि सम्पादक का संदेश — गौतम कश्यप	05
04. BRICS: A step towards a multipolar world? — Mansi Parashar	06
05. A New Model for Sustainable Development in the BRICS Framework — Alok Kumar	09
06. India-Russia Relations since 2022 — Prof. Ajay Patnaik	12
07. Economic Cooperation and Trade Relations within BRICS — Aditya Shrivastava	14
08. President Putin's vision behind BRICS' evolution into solid foundation of new world order — Vinay Shukla	16
09. Посвящается Нарендре Моді — Тимофеев Марк Иванович	16
10. Locating BRICS in the Global Order: Perspectives from the Global South (Book Review) — Ashish Singh	17
11. India in the Arctic: Past, Present, and Future — Vichare Aniket Sachin	18
12. ब्रिक्स : उपेक्षा से मान्यता तक — गौतम कश्यप	19
13. महात्मा गांधी ने दुनिया को सदा के लिए कैसे बदल दिया? — वरवरा शेरबकोव	20
14. महात्मा गांधी : अहिंसा की स्थायी विरासत — आलेसिया सवेलियेवा, मस्कवा	20
15. जानवरों के प्रति नैतिकता : महात्मा गांधी के विचारों की वैश्विक प्रासंगिता — मार्गरीटा माल्यूक	21
16. गांधी और उनके आध्यात्मिक सिद्धान्त — एलिना ज़्यागिन्त्सेवा	21
17. रूस में हिन्दी की लोकप्रियता — डॉ० इंदिरा गाज़िएवा	22
18. DISHA RAMLILA in Russia	23
19. «Пища жизни» - благая миссия для детей и для довольства Бога — Юлия Нурыевна Абдрафигин	26
20. Семейные ценности в Православии — Сизов Лев Алексеевич	28
21. Уфтожская роспись	29
22. Стихи... — Слепова Ольга Викторовна	30

प्रधान सम्पादक की कलम से...

► डॉ० रामेश्वर सिंह, पत्रकार

प्रधान सम्पादक, दिशा पत्रिका

संस्थापक, रूसी – भारतीय मैत्री संघ “दिशा”

उत्तर प्रदेश अप्रवासी भारतीय रत्न पुरस्कार, 2019

निर्माता एवं निर्देशक – पद्मश्री गेनादिपेचनिकफ मेमोरियल दिशा रामलीला, मस्कवा
सदस्य, अखिल रूसी राजनीतिक दल ‘यूनाइटेड रशिया’



प्रिय पाठकों,

आपके समक्ष ‘दिशा’ का अक्टूबर संस्करण प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। इस अंक को हमने दो महत्वपूर्ण विषयों को समर्पित किया है, जो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिदृश्य से गहराई से जुड़े हुए हैं: **“ब्रिक्स: साझा भविष्य के लिए बहुपक्षीय संवाद”** और **“रूसी संघ में परिवार को समर्पित वर्ष”**। ये दोनों विषय अपने-अपने क्षेत्रों में भले ही भिन्न हों, लेकिन एकता, सहयोग और साझा मूल्यों को बढ़ावा देने के संदर्भ में एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, चाहे वह वैश्विक स्तर पर हो या हमारे परिवारों के भीतर।

पहला विषय, ब्रिक्स, तेजी से बदलती दुनिया में बहुपक्षीय सहयोग का प्रतीक बन गया है। आज, ब्रिक्स केवल एक आर्थिक समूह ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच है, जो विभिन्न संस्कृतियों, विचारधाराओं और राष्ट्रीय हितों के बीच समवाद को बढ़ावा देता है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे ब्रिक्स देशों की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता हमें वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और स्थिरता के लिए नए दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर देती है। अब तो ब्रिक्स परिवार और भी बड़ा हो गया है, जिसमें इस वर्ष मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इथियोपिया जैसे देश जुड़े हैं।

इस साल के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में **“साझा भविष्य”** की अवधारणा पर विशेष ध्यान दिया गया है। एक वैश्विक नागरिक के रूप में, यह हमारे लिए संदेश लेकर आया है कि अब समय है जब राष्ट्रीय हितों को **“विश्व कल्याण”** और **“वसुधैव कुटुंबकम्”** के मंत्रों के साथ जोड़ा जाये। समवाद से मतभेदों को सुलझाया जाना चाहिए, और नवाचार का उपयोग सभी के हित में किया जाना चाहिए। भारत और रूस, जो ब्रिक्स के दो प्रमुख स्तंभ हैं, दशकों से दोस्ती और सहयोग के माध्यम से एक शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य की दिशा में काम कर रहे हैं, और इस मंच के माध्यम से यह साझेदारी और भी गहरी होती जा रही है।

इस अंक का दूसरा महत्वपूर्ण विषय है: **रूसी संघ में परिवार को समर्पित वर्ष**। परिवार किसी भी समाज का आधार है, और रूस में, इस वर्ष को पारिवारिक मूल्यों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए समर्पित किया गया है। परिवार की भूमिका, खासकर जब समाज तेजी से बदल रहा हो, तो और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह परिवार ही है जो हमें मूल्यों और संस्कारों से जोड़ती है, हमारी पहचान बनाती है एवं भावी पीढ़ियों के लिए स्थायी आधार एवं सुरक्षा प्रदान करती है।

विगत तीन दशकों से रूस में रहते हुए मैंने रूसी संस्कृति में परिवार की अद्वितीय और गहरी भूमिका को नजदीक से देखा है। 2024 में राष्ट्रपति पूतिन द्वारा घोषित **“परिवार को समर्पित वर्ष”** हमें यह याद प्रेरित करता है कि हमें अपने परिवारों और प्रियजनों की भलाई में निवेश करना चाहिए, अंतर-पीढ़ीगत संबंधों की कड़ी को मजबूत करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी अगली पीढ़ी को एक करुणामयी, समझदारी से भरी, शांतिप्रिय और एकजुट दुनिया मिले।

अंत में, मैं अपने पाठकों से आग्रह करता हूँ कि वे इन दोनों विषयों पर गहराई से विचार करें। ब्रिक्स परिवार जहाँ हमें मिलकर अपनी अंतरराष्ट्रीय और घरेलू समस्याओं को सुलझाने का मंच प्रदान करता है, वहीं परिवार को समर्पित वर्ष हमें स्थानीय रूप से, अपने घरों और समुदायों में ठोस कार्य करने की प्रेरणा देता है। ये दोनों विषय हमें याद दिलाते हैं कि एक उज्ज्वल और साझा भविष्य न केवल अंतरराष्ट्रीय सहयोग से, बल्कि हमारे परिवारों की मजबूती से भी आकार लेता है।

दिशा के प्रति आपके निरंतर सहयोग के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे आशा है कि यह संस्करण आपको विचारशील चर्चाओं के लिए प्रेरित करेगा कि हम सब मिलकर कैसे एक बेहतर, समृद्ध और एकजुट दुनिया का निर्माण कर सकें।

हमें दिशा के अगले अंक के लिए आपकी रचनाओं का बेसब्री से इंतजार रहेगा।

सादर,

डॉ० रामेश्वर सिंह

Call for Contributions!

Disha, a prestigious trilingual publication by the Russian-Indian Friendship Society ‘Disha’, invites you to be part of our special January 2025 edition titled **"History and Art Expedition of the Roerich Family."**

We welcome scholars, researchers, and creatives to submit research papers, articles, essays, and poems that delve into the remarkable journeys of the Roerich family.

Submission Guidelines:

- Languages: Hindi, English, Russian
- Article Length: Research articles (3,000–5,000 words); Essays (1,500–2,000 words)
- Format: MS Word, MLA citation style
- Deadline: 25th December 2024
- Email: disharusjournal@gmail.com

राजदूत
AMBASSADOR
ПОСОЛ



भारत का राजदूतावास, मॉस्को
EMBASSY OF INDIA
MOSCOW
ПОСОЛЬСТВО ИНДИИ
МОСКВА

MESSAGE

11 October 2024

I am delighted to learn that DISHA is publishing a special edition to celebrate BRICS 2024 and the 'Year of the Family.'

As a founding member of BRICS, India attaches great importance to BRICS, which has evolved into a vital platform for consultation and cooperation among Member-States. The expansion of BRICS has added even more vitality to the group, reflecting movement towards a multipolar world.

The Special and Privileged Strategic Partnership between India and Russia has made notable strides across various sectors such as trade, investment, energy, defense, and space. Notably, in the last two years, bilateral trade has not only exceeded the \$30 billion target initially set for 2025, but more than doubled.

The Russian-Indian Friendship Society, DISHA, has been a key partner in fostering strong people-to-people ties between India and Russia, highlighting our shared cultural heritage and supporting new initiatives. DISHA has also been instrumental in promoting inclusivity within the Indian diaspora.

As we enter this vibrant season of Indian festivities, I wish everyone a joyful festive season and prosperity, peace, and happiness.


(Vinay Kumar)

Highlights from Disha's Recent Events in Photos...



अतिथि सम्पादक का संदेश

► गौतम कश्यप
(रूसी अनुवादक)
Gautam@Kashyap.ru



प्रिय साथियो!

हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हम आपके हाथों में दिशा पत्रिका का अक्टूबर अंक सौंप रहे हैं। कुछ असुविधाओं के कारण पत्रिका का प्रकाशन थोड़े समय के लिए बाधित हो गया था, लेकिन अब आगे हम इसे पुनः जारी रखने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पत्रिका के पिछले विशेषांकों को आप सभी ने बहुत सराहा, और पाठकों से निरंतर यह मांग आ रही थी कि पत्रिका को और भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जाए। इसी विश्वास के साथ, हम दिशा पत्रिका को और भी सशक्त और ज्ञानवर्धक बनाने की कोशिश में लगे हैं, ताकि यह भारत-रूस मैत्री के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।

इस बार हमने पत्रिका की पुनः लांचिंग अक्टूबर माह में की है, और यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि हर अंक समय पर आपको विविध विषयों के साथ मिले। अक्टूबर का यह माह कई दृष्टियों से विशेष महत्व रखता है। हम 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाते हैं। साथ ही, भारत और रूस, दोनों ही देशों में इस साल 9 अक्टूबर को महान रूसी दार्शनिक और चित्रकार महर्षि निकलाई रेरेख का

150वां जन्मोत्सव भी मनाया जा रहा है। इसके अलावा, रूस की अध्यक्षता में इसी महीने ब्रिक्स सम्मेलन का भी आयोजन हो रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण घटना है। राष्ट्रपति पूतिन ने इस वर्ष को **“रूसी संघ में परिवार को समर्पित वर्ष”** के रूप में घोषित किया है, जिसका उद्देश्य पारिवारिक जीवन की महत्ता और सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना है। गांधी जी के अनुसार, परिवार समाज की बुनियादी इकाई है, और स्वस्थ पारिवारिक जीवन समाज में शांति, प्रेम और अहिंसा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। उनके ये विचार ब्रिक्स देशों के लिए भी प्रासंगिक हैं, जो सामाजिक स्थिरता और विकास को मजबूत बनाने के लिए पारिवारिक मूल्यों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। परिवार, गांधी जी के लिए, व्यक्तिगत और सामूहिक नैतिकता का प्रशिक्षण स्थल था। रूसी सरकार द्वारा परिवार को समर्पित वर्ष के दौरान पारिवारिक संबंधों में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना, एक तरह से गांधी जी के विचारों की ओर लौटने जैसा है। गांधी जी के अनुसार, एक आदर्श परिवार वह है जहाँ सदस्यों के बीच प्रेम, परस्पर सहयोग, और नैतिकता के मूल्य विद्यमान

होते हैं। हम ब्रिक्स को भी एक परिवार मानते हैं और इन्हीं मूल्यों की कामना अपने इस परिवार के अंदर भी करते हैं। इस अंक के लिए कई रूसी युवाओं ने महात्मा गांधी पर हिन्दी में लेख लिखे हैं, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि गांधी जी का दर्शन आज भी दुनिया भर में प्रासंगिक और प्रेरणादायक है।

वर्तमान में, दिशा पत्रिका एक ऐसा मंच है जो भारत और रूस की आम जनता को आपस में जोड़ने तथा दोनों देशों के बीच मित्रता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहा है। हमारा अनुरोध है कि आप इस पत्रिका से जुड़े रहें, तथा इस मंच के माध्यम से अपने अनुभव, शोध और ज्ञानवर्धक लेखों को हिन्दी, रूसी, या अंग्रेजी भाषा में हमारे सभी पाठक साथियों के साथ साझा करें। आपके समर्थन से दिशा पत्रिका अपने उद्देश्यों की ओर और भी मजबूती से अग्रसर होती रहेगी। इस अंक में हमने ब्रिक्स, परिवार, महात्मा गांधी और रेरेख परिवार से संबंधित आलेखों और कविताओं को सम्मिलित किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह अंक आपको पसंद आएगा और भारत-रूस संबंधों को एक नई दिशा प्रदान करेगा।

सप्रेम, गौतम कश्यप

BRICS: A step towards a multipolar world?



Mansi Parashar

PhD scholar, RUDN University
mansiparashar123@gmail.com

Abstract: A multipolar world has been a dream for most major players in international relations. Russia, in particular, has advocated for a multipolar world since the rise of American hegemony. The list of advocates for a multipolar world has grown with the emergence of regional powers, including the other BRICS members besides Russia. BRICS was formed to promote the idea of a multipolar world by balancing traditional Western influence and establishing a platform for major regional powers to communicate and collaborate. This paper aims to examine the extent to which BRICS has achieved its purpose by analysing the historical development of BRICS as an intergovernmental organization since its formation. The research primarily uses primary and secondary data, as well as literature written by international relations experts.

Keywords: Regional powers, Developing countries, Influence, Cooperation, Development.

Establishment of BRICS: Purpose and Origin

Interestingly, the term BRIC, which would take on significant meaning in international relations, was first coined by Jim O'Neill, an economic researcher at Goldman Sachs, to categorise large, fast-growing developing countries in purely economic and financial terms. This occurred in 2001, when the world was defined as unipolar, led by the United States in every sphere.

However, if we trace back the idea of multipolarity, we find the struggling leadership of Russia in the late 1990s under then-Prime Minister Yevgeny Primakov. He proposed the idea of RIC (Russia, India, China), which made some progress by holding annual trilateral meetings at the foreign minister level since 2001 to discuss non-traditional security issues

like migration, trafficking, and terrorism. In 2006, the Brazilian foreign minister was invited to join the RIC foreign ministers' meetings; this invitation and the idea of including Brazil came from Russian Foreign Minister Sergei Lavrov. However, these meetings were largely informal in 2006 and 2007. The year 2008 witnessed the first formal meeting among the BRICs foreign ministers in Yekaterinburg, Russia, which was again a Russian initiative.

The 2008 financial crisis proved to be a turning point for the legitimacy of developing countries and their contest for power, as developed countries faced profound financial crises while developing countries maintained relative economic stability. Within two months of Lehman Brothers' bankruptcy, the BRIC finance ministers and central bankers met in Brazil, and within the following four months, they met four times. This served as a foundation for these countries to become agenda setters at the April 2009 G20 summit. In late November, the first BRICs summit was announced to be held in Russia in 2009. Thus, the 2008 financial crisis laid the groundwork for the political dimension of BRIC.

The agenda of the first BRICs summit included discussions on reforms in international institutions, especially financial institutions like the World Bank and the International Monetary Fund (IMF), which were and still are considered puppets of the West. Another key theme was reducing global dependence on the US dollar by decreasing US dollar assets in their existing reserves; the Russian government was eager to discuss ways to limit the use of US dollars in intra-BRIC trade. However, the main objectives of the summit revolved around development issues and plans, ranging from science and education to natural disasters.

Development of BRICS as an intergovernmental organization

The results of the first BRICs summit and the roles these countries played during the 2008 financial crisis and the following G20 were visible in the IMF quota reforms of 2010, which included the BRIC economies among the ten largest members of the IMF for the first time. By 2010, BRIC was already receiving formal and informal membership requests from several countries, such as Mexico, Indonesia, and Turkey. Just before the second BRICs summit in Brazil, the IBSA (India, Brazil, South Africa) summit was held in Brazil, allowing South African President Jacob Zuma to hold bilateral meetings with all BRICs leaders individually, which proved fruitful and ultimately turned BRIC into BRICS. This development altered the character of the intergovernmental grouping by making it a secure global alliance representing all major regional powers of the developing continents. The inclusion of an African country symbolised the inclusive nature of BRICS as an organization.

The third BRICS summit in Sanya, China (2011), symbolised their rising interest in commenting on and showcasing their dissatisfaction with the manner in which the intervention in Libya was carried out. Another influence on this rising interest was the presence of all BRICS countries in the UN Security Council at that time. This summit concluded with the production of an action plan, signaling that BRICS sought to be more than a consulting group and aimed to strengthen cooperation and work together in various spheres like education, international security, finance, and agriculture.

The fourth BRICS summit in New Delhi, India (2012), marked the beginning of the institutionalisation phase of BRICS by putting forth the idea for a BRICS Development Bank

(BDB), as there was disappointment with the pace of reforms in global financial institutions. The interaction among BRICS had broadened from merely intergovernmental to include working groups, think tanks, businesspeople, and others. This summit even went so far as to warn the collective West and Israel against military action over Iran's controversial nuclear program and criticised developments in Syria.

By the time of the fifth BRICS summit in Durban, South Africa (2013), the significance of BRICS was established to the extent that the Syrian President was asking them to mediate in the conflict in his nation. However, this can also be explained by the close Russian ties with Assad's government and China's interest in the Middle East, which might have prompted Assad to seek BRICS allegiance. This summit also attempted to include African countries in one of its forums, the "BRICS Leaders-Africa Dialogue Forum," which can be seen as an active effort to establish the significance of BRICS on the African continent.

It was during the sixth BRICS summit in Fortaleza, Brazil (2014), that Western media took great interest as the idea of the BDB was being realised in the form of the New Development Bank (NDB), and a Contingent Reserve Arrangement (CRA) was also being established. The institutionalisation of BRICS can be seen as a major step away from Western influence and Western-influenced financial institutions.

The Western attempts to isolate Russia after the annexation of Crimea gave a new geopolitical purpose to BRICS, as its members decided to take a firm stand against such actions. For instance, when Australia threatened to exclude Russia from the G20, BRICS issued a collective statement in favor of Russia and the concept of

multipolarity.

The seventh BRICS summit in Ufa, Russia (2015), saw changes in the national situations of the BRICS members. While Russia, Brazil, and South Africa were undergoing political unrest, India, under newly elected Prime Minister Narendra Modi, and China were continuing to flourish. BRICS' stance on the annexation of Crimea invoked accusations from the rest of the world of being biased and selective about breaking the rules. This summit marked the inauguration of the NDB and CRA. Although there was a delay of five years, the IMF reforms approved in 2010 were finally implemented in 2016, showcasing the relevance of BRICS in influencing international organizations.

The next BRICS summit in Goa, India (2016), witnessed a contrast in the economic situations of the BRICS member countries. On one hand, India was on track to become one of the fastest-growing economies, while Brazil faced severe economic and diplomatic problems. Despite this contrast, the goals aligned, and the summit proved to be a success.

The prelude to the ninth BRICS summit in Xiamen, China (2017), was quite disturbing, as a border standoff occurred between India and China when China began building a road in a disputed area. However, the legitimacy of BRICS was again proved when India and China agreed to pull back their troops, defusing tension right before the summit. Another major focus of this summit was strengthening people-to-people exchanges. The list of terrorist groups over which BRICS expressed concern included Pakistan's Lashkar-e-Taiba, which was seen as a win for India's diplomacy against Pakistan.

The tenth and eleventh BRICS summits, hosted under the newly elected presidents of the nations in Johannesburg, South Africa (2018),

and Brasilia, Brazil (2019), showcased that the change in leadership did not affect the inclination of member countries toward BRICS. The leaders also saw this as a platform to address the international community. The tenth summit saw increased cooperation in emerging technologies by establishing the "BRICS Network of Science Parks, Technology Business Incubators, and Small and Medium-Sized Enterprises." Additionally, the summit announced an expansion of NDB operations by establishing a Project Preparation Fund and a regional office in São Paulo, Brazil.

The twelfth BRICS summit was supposed to be held in St. Petersburg, Russia (2020), but due to the outbreak of the global COVID-19 pandemic, it took place in the format of a video conference. This clearly indicated the willingness of the leaders to maintain momentum and continuity. The declaration focused on marking the 75th anniversary of the UN, reinforcing their trust in multilateral institutions, and calling for global peace in the backdrop of the COVID-19 pandemic. Two innovative institutional establishments occurred during this summit: first, the BRICS Rapid Information Security Channel (BRISC), which would allow the central banks of the member countries to tackle cybersecurity; second, the BRICS Local Currency Bond Fund.

The thirteenth BRICS summit, hosted by India (2021), was again virtual due to the COVID-19 pandemic, which was the main highlight of the summit.

During the fourteenth BRICS summit, hosted virtually by China (2022), two important regional players applied for membership in BRICS, namely Iran and Argentina, clearly depicting the increasing value of BRICS in international relations. A key issue of BRICS concern was the



Ukrainian crisis; the member states encouraged diplomacy and communication. However, China, India, and South Africa chose not to participate in the voting held in the United Nations denouncing Russia's invasion of Ukraine. Another key highlight was the continuing discussions on post-pandemic economic recovery.

The most recent BRICS summit, hosted by South Africa (2023), saw an expansion as 40 countries expressed interest and 23 formally applied for membership. Six of them—Argentina, Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, and the UAE—were invited to become full members of BRICS on January 1, 2024.

Also, the Russian President's decision to attend the summit virtually marked a level of maturity among the member states. His virtual presence did not affect relations among the members, as his physical presence might have diverted attention in a different direction.

Future of BRICS

The interests, values, and ambitions of the BRICS countries do not always align and, in some cases, even lie in opposite directions. From an economic perspective, Russia, as a major oil exporter, benefits from high energy prices, whereas India, as a major oil importer, suffers due to this. Even in political terms, Brazil, India, and South Africa are ardent followers of democracy, while Russia has a presidential democracy combined with oligarchic practices, and China has an authoritative communist regime. On one hand, Brazil and India aim for a power distribution in international organizations, while Russia and China are not as enthusiastic, given their permanent membership in the Security Council, which has benefited them over the years. China emphatically opposes Brazil and India's campaign to gain permanent UNSC

membership. There are also concerns among member states about intra-BRICS trade imbalances, which were raised during the tenth BRICS summit in Johannesburg.

Some of BRICS' victories in their fight for multipolarity remain incomplete, such as the unanswered demand for democratising the IMF.

One characteristic of BRICS that ensures close ties, cooperation, and a continued threat to the West by strengthening the idea of multipolarity is that BRICS leaders and ministers continue to meet on the sidelines of other international events to discuss contemporary issues. For instance, BRICS leaders met in Hangzhou, China, on the margins of the G20.

The bilateral relations among BRICS countries can also be seen as a hindrance to aligning their decisions. The most significant of these is the India-China relationship, as both countries have issues with each other, ranging from border conflicts in the Ladakh region and the state of Arunachal Pradesh to maritime conflicts in the Indian Ocean region, trade-related issues, and cybersecurity concerns.

However, despite various issues within and among BRICS, the countries have managed to make firm decisions, strengthen cooperation, fulfill promises, and further the objectives of BRICS as an organization. BRICS has remained stable despite instability in Russia caused by the Ukrainian crisis; in fact, except for Brazil, all other BRICS countries abstained from voting in the UN General Assembly. BRICS has also allowed Russia to demonstrate that it is not isolated despite Western attempts to do so. Even changes in national leaders and their beliefs did not shake the role and importance of BRICS, whether it was the power shift in Brazil from leftist to rightist and back to leftist or changes in leadership in

India. Thus, the future of BRICS appears bright enough to ensure its growth in international relations despite all its problems and shortcomings.

Conclusion

The fact that Western hegemony and influence are being questioned makes it safe to state that the global order is undergoing a transition from a unipolar to a multipolar world. Assessing the extent to which BRICS has played a role in this transition is the purpose of this paper.

The collective actions taken by BRICS have ensured that the West no longer holds sole authority over global issues, promoting a more democratic functioning of international organisations. The voices of the Global South are being heard, and their problems are being addressed, with discussions on global threats such as diseases, cybersecurity, and terrorism taking place at all levels.

The rise of regional powers in terms of economics and influence has led to the increasing importance of BRICS on the global stage, while the rise of BRICS has also enhanced the diplomatic standing of these regional powers. However, BRICS serves primarily as a platform for promoting the idea of multipolarity, and in that sense, it is certainly developing its influence.

To conclude about the extent to which BRICS has succeeded in establishing multipolarity in the global order, it can be said that it has certainly shaken Western hegemony and established the beginning of an era of multipolarity.

References:

1. Preamble. 2020 Moscow Declaration. <http://www.brics.utoronto.ca/docs/201117-moscow-declaration.html>
2. XIII BRICS summit- New Delhi declaration. Ministry of External Affairs, Government of India. https://www.fsi.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl%2F34236%2FXIII_BRICS_Summit_New_Delhi_Declaration
3. Kugiel, P. (2022) The relevance of BRICS after the Russian invasion of Ukraine. The Polish institute of International Affairs. <https://www.pism.pl/publications/the-relevance-of-brics-after-the-russian-invasion-of-ukraine#:~:text=Most%20of%20the%20BRICS%20countries,rest%20of%20the%20group%20abstained>
4. Kumar, R. (2023). BRICS: 15th summit and beyond | manohar parrikar institute for defence studies and analyses <https://idsa.in/issuebrief/BRICS-15th-Summit-and-Beyond-RKumar-280823>
5. Press release: Historic quota and governance reforms become effective. IMF. (2016, January 27). <https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/14/01/49/pr1625a>
6. Stuenkel, O. (2021) The BRICS and the future of Global Order. Lanham: Lexington Books.

A New Model for Sustainable Development in the BRICS Framework



Alok Kumar

Group Chairman, AKIS TECH LTD
Hony. Gov. Body Member and Director for Russia, BRICS Chamber of Commerce and Industries
President (Russia and Central Asia), Economic Council of India
Director (Asia Pacific), International Congress of Industrialists and Entrepreneurs (ICIE)

The BRICS countries, accounting for over 40% of the world's population, have made significant progress in the last few years toward sustainable development. Sustainable development is the key to the long-term prosperity of these nations, and it is essential for them to work together to achieve their goals. According to the United Nations, sustainable development is “development that satisfies present needs while still preserving the ability of future generations to meet their own needs.” This means that economic development must be balanced with social and environmental considerations. BRICS’ approach to coopera-

tion on renewable energy, as well as the results of these actions, is noteworthy.

Despite the spread of multiple frameworks focused on climate change, such as the United Nations’ (UN) 2030 Agenda for Sustainable Development, and the clear relevance of the local level in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), territorial governance for sustainability still struggles to take tangible actions that consider the holistic interactions between climate, environment, and society.



BRICS countries have a shared vision of sustainable development that prioritises economic growth, social development, and environmental sustainability. We should note that this vision is based on the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), which were adopted in 2015 and provide a framework for global sustainable development efforts.

The BRICS nations have recognised the importance of international cooperation in achieving their sustainable development goals. They have committed to pursuing it in a way that is inclusive, equitable, and environmentally responsible. The BRICS states have several key priorities where sustainable development plays a role. First, the promotion of sustainable and inclusive economic growth. They recognise that economic growth is essential for poverty reduction and improving living standards, but that it must be achieved in a way that is socially and environmentally responsible. They are

committed to promoting sustainable industrialisation, investment in infrastructure, and the development of the digital economy.

Second, environmental sustainability. BRICS nations observe the urgent need to address climate change and protect the environment and are committed to promoting renewable energy, sustainable agriculture, and biodiversity conservation. Third, the promotion of social development and the reduction of inequality. They are committed to promoting gender equality and empowering women, recognising that gender inequality is a barrier to sustainable development.

In order to demonstrate how the BRICS countries see sustainable development, we provide the following statistics. According to the International Monetary Fund (IMF), the combined GDP of BRICS nations was \$18.5 trillion in 2020, representing 23% of global GDP. In terms of renewable energy in 2020, the BRICS nations accounted for 41% of



global renewable energy capacity, with China leading the way with 792 GW of installed capacity. In recent years, the BRICS nations have made significant strides in reducing their carbon emissions. China, for example, reduced its carbon intensity (the amount of carbon emitted per unit of GDP) by 48.4% from 2005 to 2020, while India reduced its carbon intensity by 21.4% over the same period. Moreover, states are making significant strides in promoting sustainable urbanisation, with China investing \$200 billion in green infrastructure as part of its post-pandemic recovery plan. One of the key areas where the BRICS nations have made significant progress in sustainable development is renewable energy. In 2019, China, Brazil, and India were among the top five countries in the world in terms of renewable energy capacity installed. China alone accounted for 30% of the global capacity installed, with India and Brazil contributing 10% and 5%, respectively. "All the BRICS countries are emerging economies facing carbon reduction challenges, and there is great scope for energy cooperation, especially in renewable energy," mentioned Luo Zuoxian of the Sinopec Economics and Development Research Institute.

Another area where the BRICS nations are making significant progress in sustainable development is in reducing their carbon emissions. China, the world's largest emitter of greenhouse gases, has set a target of peaking its emissions by 2030 and achieving carbon neutrality by 2060. Brazil, Russia, India, and South Africa are also taking steps to reduce their carbon emissions and increase their use of renewable energy sources. Moreover, the BRICS nations are also making progress in sustainable urbanisation. China, for example, has implemented a number of policies to promote sustainable urban development, including the construction of green buildings and the development of public transportation systems. India is also making progress in this area, with the government's Smart Cities Mission aimed at promoting sustainable urban development.

Based on the key areas of development, the participating countries hold regular events related to sustainable development in the BRICS countries. For example, BRICS in

2021 launched the BRICS Green Fund, a joint initiative to finance green projects and promote sustainable development. The fund will focus on financing renewable energy, energy efficiency, and other environmentally sustainable projects in the BRICS nations. This year, India also initiated the National Hydrogen Energy Mission, a scheme that promotes the exploitation of hydrogen as an environmentally friendly energy source. The next important step is South Africa's Renewable Energy Program, which has attracted significant investment from international companies and has helped to reduce South Africa's dependence on fossil fuels. In 2021, China launched its national carbon trading system, the largest in the world. The system aims to reduce carbon emissions by incentivizing companies to reduce their carbon footprint. Consequently, these initiatives demonstrate that the BRICS nations are taking concrete steps to promote economic growth, social development, and environmental sustainability.

Russia's contribution to BRICS sustainable development cannot be ignored. Russia is an active participant, and here are some examples of Russia's input. The country has significant potential for renewable energy, particularly in wind and solar power. Russia has set a target of increasing the share of renewable energy in its total energy mix to 4.5% by 2024. Russia has also initiated several projects to promote the development of renewable energy, such as the construction of wind and solar power plants in various regions. As one of the world's largest wheat producers, it has implemented several programs to promote sustainable agricultural practices. With regard to climate change mitigation, Russia has taken steps to reduce greenhouse gas emissions, especially in the energy sector. The country has implemented several energy efficiency programs and set emission reduction targets in various sectors. Russia has also ratified the Paris Agreement on climate change and has pledged to reduce emissions by 30% by 2030 compared to 1990 levels. Overall, the member is making significant efforts to promote

sustainable development in the BRICS nations.

The prospects for sustainable development in the BRICS nations are highly promising and reflect the ambitious goals of the group. The adoption of renewable energy sources, such as solar and wind power, is a key aspect of the BRICS nations' sustainable development strategy. Moreover, the BRICS nations are among the largest agricultural producers in the world, which makes the promotion of sustainable agricultural practices essential to reduce environmental impacts, improve food security, and increase farmer incomes. Many experts broadly agree that the BRICS nations have an important role to play in promoting sustainable development and shaping the global sustainability agenda.

However, despite the many benefits of sustainable development, there are still several challenges that the BRICS nations must address. Social inequality, environmental degradation, and climate change are critical issues that require a concerted effort and cooperation among these nations. Thus, cooperation among the BRICS nations holds great promise for addressing the challenges and realising the opportunities of sustainable development. By working together, the BRICS nations can create a sustainable future for their citizens and for the planet as a whole.

Climate change and biodiversity depletion are among the most pressing issues facing the world today—triggering economic transformation, driving fundamental business model change, and leading to a rethink of what business as usual looks like. Business commitments to reach net-zero emissions and reduce their impacts on the planet have increased rapidly. As the global push toward decarbonisation accelerates and the impacts of climate change play out

globally, businesses are preparing for a low-carbon future—rising to stakeholder demands for accountability on plans, action, and progress. Strong decarbonisation targets and robust transition plans to decarbonise business operations and supply chains, together with targets and actions to reduce impacts on nature, are now expected. Boards are under significant pressure to address environmental issues, and it is critical that businesses grasp the implications of climate and nature risks and opportunities.

The Net Zero Readiness Index in 2021, a few weeks before the COP26 UN climate change conference in Glasgow, resulted in 153 countries putting forward new emissions targets for 2030, with more than 90 percent of world economic output and global emissions being covered by net zero agreements. Attempts to phase out the use of coal, the single biggest contributor to climate change, failed with weaker language to 'phase down' its use in the final agreement. COP26 kept alive the hope of keeping global temperature increases within 1.5 degrees Celsius this century but added, "its pulse is weak."

The last two years have seen many countries taking steps in the right direction toward net zero, even if most have a long way to go. Some have announced significant new policies to support decarbonisation, including REPowerEU in Europe. Emissions trading schemes are expanding in several countries, and the EU is phasing in its Carbon Border Adjustment Mechanism, an idea that other countries look likely to adopt. The bloc is also introducing regulations to block the import of products linked to deforestation, showing how some jurisdictions plan to go further and faster to meet net zero pledges.

Circular Economy

Society has long been accustomed to 'take, make, waste' methods of production, but these practices are no longer sustainable. To face the challenges of a growing world population, climate change, and resource scarcity, the world must change the way we consume—away from the linear towards a more circular approach.

Businesses are turning towards a circular economy model to help manage regulatory requirements and generate sustainable growth opportunities that deliver ESG benefits. This creates greater efficiency and profitability, less waste, better innovation, and stronger relationships with stakeholders.

Collaboration is critical to the success of more circular ecosystems, and global reach enables our professionals to advise clients as they shape and develop new circular strategies and business models. As businesses reimagine and reinvent their existing products, supply chains, and services, our teams help integrate circularity through:

- Circular strategy
- Measurement and steering
- Circular execution and delivery

Circular economy principles and programs are an engine to accelerate sustainability, and for those who want to do well in the new economy, circularity is key to remaining relevant and future-proofing their business. Adopting a circular mindset is a core part of a company's journey towards better ESG performance—in a world where we can no longer afford to use up essential resources—requiring production models that work for generations to come.

High-performing companies are realising that good and robust governance drives environmental and social responsibility. As organisations continue to adapt to an ever-changing landscape, boards and management must prepare to address the new dynamics affecting their oversight roles and the governance of their organisations. Boards have responsibilities to steer their organization toward sustainability and ensure the ESG information under their oversight is appropriate, reliable, and compliant.

While plenty of guidance and information exists, standards and regulations addressing specific areas of responsibility and reporting continue to evolve. Governance covers a wide variety of issues, including risk management and internal controls, data harvesting and data breaches, executive remuneration, board diversity and competencies, as well as shareholder rights.

India-Russia Relations since 2022



Prof. Ajay Patnaik

Former Chairperson of the Centre for Russian & Central Asian Studies and Former Dean of the School of International Studies JNU, New Delhi

Introduction

Prime Minister Modi's high-profile visit to Russia on 8 July 2024 to hold the 22nd India-Russia annual summit with President Vladimir Putin was a very significant event for the relations between the two countries. The warmth displayed when the two leaders met captured the attention of the world. This was Prime Minister Modi's first trip since the start of Moscow's operations in Ukraine. The two countries discussed ways to further shore up bilateral cooperation in sectors such as energy, trade, manufacturing and fertilizers. Prime Minister Modi was officially conferred the 'Order of St Andrew the Apostle' award by President Putin on July 9 for his contribution to fostering bilateral ties between the two countries.

The visit and the bonhomie did not go down well with the US and its partners. There are many reasons why the US and the West are quite upset with India and this has been conveyed to India at various points of time. India did not vote against Russia in the UN or any other forum. India prevented Western countries from making the Ukraine conflict the center point of the G-20 agenda. Due to India's role, the final Declaration at the G-20 Summit in New Delhi on 10 September 2023 did not condemn Russia.

India played its part at various levels to prevent Russia's political and economic isolation. India's trade and economic relations with Russia are growing exponentially. Politically and diplomatically, India has stood with Russia despite the enormous pressure of the Western alliance. Russia offered oil at discounted prices and the trade in local currencies. This has boosted Indo-Russian trade to record levels. The increasing amount of oil being purchased by India from Russia despite Western sanctions is another factor why the West is getting increasingly impatient with New Delhi.

Ukrainian President Zelenskyy had criticised Modi's visit to Russia, saying it was a "huge disappointment and a devastating blow to peace efforts to see the leader of the world's largest democracy hug the world's most bloody criminal in Moscow on such a day". He was referring to the incident in which a missile, allegedly fired from the Russian side, hit a children's

hospital. Such statements have not gone down well with the Indian public and does not dampen the spirit of India-Russia friendship.

Though Modi followed his Moscow visit by a visit to Kiev, it was not the same by any comparison. While India's visit to Moscow was within the bilateral strategic partnership format, the trip by Modi to Kiev was clearly intended to restore some degree of balance so that it does not appear to be taking sides in the conflict, which obviously it is not. But in the opinion of the West, any country getting close to Russia helps Moscow in its aggression. India, thus, would like to dispel this impression. The visit to Kiev on 23 August was intended to be helpful in that context. The Indian Prime Minister did not go directly to Ukraine. He landed in Kiev by a train after a two-day visit to Poland. The visit to Kiev lasted a few hours.

Kiev had unrealistic expectations from New Delhi. Ukrainian President Zelensky on August 23 said that his Russian counterpart Vladimir Putin "will be forced to stop the war" in Ukraine if India changes its stance. His remarks came during a press conference after his meeting with Prime Minister Narendra Modi who was on a short visit to Kiev. "If India and Indians change their stance (towards Russia), the war can be stopped; Putin will be forced to stop the war," President Zelensky said.

Despite repeatedly calling for a ceasefire and peace in Ukraine in both capitals (Moscow and Kiev), New Delhi has refrained from condemning Russia's operations. India seeks to maintain and strengthen relations with Moscow – a major supplier of its arms and a longstanding partner, that could be a key to balancing its strained relationship with China. India has also acted as an economic lifeline for Russia, ramping up purchases of its crude oil after countries around the world slapped sanctions on Moscow, isolating it economically. India overtook China as the world's biggest importer of Russian oil, according to Reuters, citing data from trade and industry sources.

Relations since 2022

Since the start of the Russian's Special Operations in February 2022, two instances exemplify the level of the relationship between Russia and India in

the present context.

On 31 March 2023 Russia adopted a New Foreign Policy Concept, which highlights the vision for a more equitable multipolar world order. Specific mention has been made of India. The Document states, "Russia will continue to build up a particularly privileged strategic partnership with the Republic of India with a view to enhance and expand cooperation in all areas on a mutually beneficial basis and place special emphasis on increasing the volume of bilateral trade, strengthening investment and technological ties, and ensuring their resistance to destructive actions of unfriendly states and their alliances".

This came in the background of India not voting against Russia for its special operation in Ukraine either in the UN General Assembly or in the UN Human Rights Council, despite Western push and pressure.

The second instance was when Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov praised India and said that at the G-20 summit in August 2023 New Delhi prevented Western countries from making the Ukraine conflict the center point of its agenda.

India as the President of the G-20 faced a lot of pressure from the West to take a stand against Russia. However, it can be said that India has very diplomatically managed to preserve its neutrality. Unlike the 2022 "G20 Bali Leaders' Declaration", the final document of the 2023 summit (Delhi Declaration) refrained from deploring Russia for its actions in Ukraine. The 'Bali Declaration' had demanded "complete and unconditional withdrawal" of Russia's armed forces from the territory of Ukraine. The 'Delhi Declaration', however, made no such demand on behalf of the G-20.

The positions and actions of Russia and India have a big impact on the making of the world order, which until recently have been defined as unequal and unjust. Though the efforts to remake the world order and make it multipolar have been going on for the last many years through the formation of forums like the SCO and BRICS, the process seems to move fast forward since 2022. For India, multipolarity provides 'strategic autonomy'.

India-Russia oil trade, local currency use and De-dollarisation.

Multipolar world order also depends upon changes in the global financial order, that requires not just pushing back against the Western domination of the global financial institutions but also limiting the influence of the US Dollar as the global reserve currency. The sanctions following Russian operations in Ukraine have forced countries to look for alternative arrangements to continue trade with Russia and those steps could lessen the role of the Dollar in the global economy.

Following Western sanctions, Russia made a quick shift over to trade in Ruble and in other local currencies with friendly countries. In July 2022, the Reserve Bank of India put in place a mechanism to facilitate international trade in Rupees (INR), with immediate effect. Arrangement for invoicing, payment, and settlement of exports/imports in INR were put in place. This would facilitate India's trade with countries under sanction like Iran and Russia by easing payment issues with these states.

Russia offered oil at discounted prices to friendly countries and the trade in local currencies. This has boosted Indo-Russian trade to record levels. Russian oil exports to India, the world's third-largest crude importer after China and the US, climbed record levels. Russia's share of India's oil imports increased significantly from less than 1% of India's energy market in 2021 to 35% of India's total oil imports. By February 2023 Russia had replaced Iraq and Saudi Arabia from the top of the list. In May 2023, the volume of crude imports from Russia had increased to 2.16 million barrels per day. India's oil trade with Russia has meant a shift to other currencies that could prove lasting.

India is seeking to reduce its over-reliance on the US dollar by diversifying its currency reserves and conducting transactions in alternative currencies. For developing countries like India, de-dollarisation offers potential benefits such as reduced vulnerability to US monetary policy fluctuations, enhanced monetary autonomy, and improved financial stability through the diversification of foreign currency reserves.

Russia-India: Looking Ahead

From Russia's perspective, India is a very valuable partner that can play a bigger role in the global stage. From being a market of Soviet arms, today both are jointly producing military hardware and intend to sell it to third countries. It is clear that Russia wants India to be a major power in Asia for which defence, economic and trade co-operations between them are necessary. With Indo-Russian trade growing by leaps and bounds, focus is

shifting to transport corridors between India and Eurasia. The International North-South Transport Corridor (INSTC) has suddenly acquired significance and is expected to boost trade between Russia and India. Azerbaijan, Iran, Kazakhstan and Turkmenistan would benefit with this link.

While long years of close friendship have created sufficient trust between Russia and India, some new issues in the post-Soviet period are also pushing them for closer cooperation. The annual strategic summit between the highest leadership of both countries since 2000 has been extremely helpful in removing any misgiving among them and expanding the range of the relations, like the building of nuclear reactors and joint production of highly sophisticated military systems including fighter aircrafts and missiles.

In our opinion, countries like India are also seeing signs of their efforts bearing fruit. BRICS is becoming a major international forum to bring together emerging economies and countries of the Global South. More countries are showing interest to join BRICS. India's trade and economic relations with Russia are growing exponentially. Politically and diplomatically, India has stood with Russia despite the enormous pressure from the Western alliance. India understands that any form of Western success in Ukraine will be a huge setback to creating a just and multipolar world order. That is why India has diplomatically, politically and economically stood firmly with Russia.

Russia's trade with India is booming and bilateral payments are proceeding smoothly without the glitches that have been hampering trade with other countries. Anatoly Popov, deputy CEO of Russia's largest lender, Sberbank, told Reuters. Sberbank handles payments for up to 70 percent of all Russian exports to India. Russia's trade with India nearly doubled to \$65 billion in 2023, with the south Asian country becoming a major importer of Russian oil after the imposition of Western sanctions on Moscow in 2022 over the conflict in Ukraine.

"In 2022, there was a significant increase in the interest of Russian businesses in the Indian market because this market serves as an alternative," Popov told Reuters in an interview ahead of the Eastern Economic Forum, an economic conference targeting Russia's Asian partners.

"Today, we are opening accounts in rupees for Russian clients as well. We do not rule out the possibility that, in addition to being a means of payment, the rupee may also become a means of savings," he added. Sberbank's branch in India has offices in Delhi and Mumbai, as well as an

IT center in Bangalore. The number of staff in its Indian offices increased by 150 per cent this year, having said in April they wanted to hire 300 IT personnel for the hub in Bangalore. Sberbank said transactions in rubles and rupees were proceeding smoothly, with 90 percent of them taking only a few hours to complete. This is in stark contrast to other trading partners such as China.

Popov said growing Indian exports to Russia had helped solve the problem of surplus rupees held by Russian companies, which hampered bilateral trade in 2023, as rupees were used to pay for imports from India. (Business Standard, 3 September 2024)

Over the past 12-15 months, the funds held by Russian companies in rupee vostro accounts in India have nearly halved to approximately \$3-3.5 billion. Initially totalling around \$8 billion, these funds were used for expenditures on Indian securities, machinery, and defence products. During the last financial year and the current one, a considerable portion of these funds has been allocated to investments and payments. (Business Standard, 5 September 2024)

Conclusion

There is no sign of the Ukraine conflict ending immediately. Of course, the role of the US and Russia is most vital to end the conflict and start the peace process. But in the future, if the situation arises, countries such as India would be useful in taking the discussions forward. India has demonstrated its strategic autonomy in the last two years by not severing ties with Russia despite Western pressure. Yet, it has good relations with Kiev as well. The West has lost all its influence with Moscow at the moment. So, countries like India, which is a leader of the global south, would be useful to play a role in fostering dialogue between the two conflicting sides.

Putin made a reference to such a possibility recently. President Vladimir Putin on 5 September 2024 named India among the three countries he is in touch with over the Russia-Ukraine conflict and said they are sincerely making efforts to resolve it. "We respect our friends and partners, who, I believe, sincerely seek to resolve all issues surrounding this conflict, primarily China, Brazil and India. I constantly keep in touch with our colleagues on this issue," the Russian president said at the Eastern Economic Forum in Vladivostok. Separately, Russian presidential spokesman Dmitry Peskov told Russia's Izvestia daily that India could help in establishing a dialogue on Ukraine. (By Dipanjan Roy Chaudhury, Putin says in Touch with India, China, Brazil over Russia-Ukraine Conflict, Economic Times, 6 September 2024)

Economic Cooperation and Trade Relations within BRICS



Aditya Shrivastava
Founder, BHARAT ROSSIA
adityapratapsri@gmail.com

Introduction

The BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) alliance, though diverse in defined by rapid technological advancements, geopolitical realignments, and economic unpredictability, multilateralism has become not only a necessity but a vehicle for nations to navigate their shared futures. As the global economic landscape evolves, BRICS nations are increasingly focused on fostering multilateral dialogues aimed at enhancing economic cooperation and trade relations. For India, this partnership is particularly crucial as it forges deeper connections with member countries, aiming to position itself as a significant player in sectors such as pharmaceuticals, space exploration, and cybersecurity.

This year, designated as the "Year of Family" by BRICS leadership, underscores the importance of unity and collaboration, reminding us that the strengthening of trade relations is not merely an economic endeavour but also a means of bringing nations closer on the global stage.

Establishing the New Development Bank (NDB)

The establishment of the New Development Bank (NDB) in 2014 marks a pivotal moment in the economic cooperation within BRICS, headquartered in Shanghai, is not merely a financial institution but a manifestation of BRICS' commitment to an alternative global financial order. Unlike traditional multilateral financial institutions, which often impose stringent conditions on developing countries, the NDB provides member countries with the autonomy to finance infrastructure projects in alignment with their national priorities. Aimed at mobilising resources for infrastructure and sustainable development projects, the NDB serves as an alternative to Western-dominated financial institutions like the World Bank and the International Monetary Fund (IMF). With an initial capital of \$100 billion, the NDB symbolises the growing financial independence and strength of BRICS nations.

India, as a founding member of the NDB, has been instrumental in shaping the bank's priorities, particularly in addressing the infrastructure deficit across developing nations. The NDB has financed numerous infrastructure and renewable energy projects across the nation. For instance, the NDB provided a significant loan for India's ambitious solar energy expansion project, furthering its commitment to renewable energy and sustainable development. The NDB has also enabled India to finance large-scale infrastructure projects, providing much-needed funding for initiatives aimed at reducing poverty and fostering inclusive growth.

It is evident that the NDB serves as an embodiment of BRICS' ethos — to foster development that is fair, equitable, and sustainable. By focusing on infrastructure, green energy, and technological innovation, the NDB has reinforced BRICS'

standing as a group that prioritises long-term, inclusive growth. The focus on sustainable development reflects India's own domestic agenda, which emphasises renewable energy and environmental stewardship.

India's Role in BRICS Economic Relations

India, a founding member of BRICS, has been instrumental in shaping the economic discourse within the group. The nation's strategic focus has been on leveraging the BRICS platform to enhance trade relations, promote technology transfers, and boost foreign investments. The collaboration has also sought to extend beyond traditional sectors, venturing into new avenues such as pharmaceuticals, space exploration, and cybersecurity. This broad spectrum of engagement reflects the versatility and depth of BRICS' mission to foster sustainable growth.

Economic cooperation within BRICS has already shown tangible results, with trade between India and its BRICS partners witnessing exponential growth over the years. For instance, India's trade with Brazil has seen a significant uptick, particularly in areas like agricultural commodities and pharmaceuticals. Meanwhile, Russia and India's relationship in energy, defence, and space exploration continues to grow stronger, with both nations contributing to joint projects and exchanges that enhance mutual capacities.

Trade with China is, of course, a significant element of India's economic relationship within BRICS. Despite historical tensions and trade imbalances, the two nations recognise the mutual benefits of maintaining strong economic ties. In 2021, bilateral trade between India and China reached a historic high of over \$125 billion, although the trade deficit remains a point of contention. However, the real strength of India's engagement lies in its efforts to diversify its trade relationships with the other BRICS countries, such as Russia, Brazil, and South Africa. These nations, while economically less formidable than China, provide key opportunities for India to export services, technology, and pharmaceuticals. In turn, they offer access to critical natural resources, agricultural products, and markets for India's expanding economy.

Case Study: India and Russia - Expanding Horizons in Space and Cybersecurity

India and Russia's relationship has long been underpinned by strategic cooperation, particularly in defence and space exploration. The Indian Space Research Organisation (ISRO) and Roscosmos have engaged in numerous joint ventures, with the most recent being India's participation in Russia's ambitious space exploration projects. Such collaborations signal the depth of trust between the two nations and highlight the potential for further cooperation in high-tech sectors. In recent years, India has collaborated with Russia on several space

initiatives, including the Gaganyaan mission, which aims to send Indian astronauts into space with Russian assistance. Furthermore, joint space projects with Brazil and South Africa are in the pipeline, showcasing BRICS' potential to foster collaboration in cutting-edge scientific and technological fields.

This growing partnership in space exploration highlights the importance of BRICS nations pooling their resources and expertise in high-tech areas to compete globally. The collaboration not only strengthens diplomatic relations but also encourages technology transfers and innovation within the bloc.

Additionally, cybersecurity has emerged as a critical area of focus for both India and Russia. As digital threats become increasingly sophisticated, BRICS nations have acknowledged the need to cooperate in safeguarding their critical digital infrastructures. In 2019, India and Russia signed a cybersecurity pact to enhance collaboration in this domain, reflecting a broader trend within BRICS to address non-traditional security challenges collectively.

Case Study: India and Brazil - Strengthening Pharmaceutical Trade

India's pharmaceutical industry, often dubbed the "pharmacy of the world," plays a significant role in its economic relations with Brazil. Brazil is one of the largest importers of Indian generic medicines, making healthcare affordable for millions. In return, Brazil exports commodities like crude oil, gold, and sugar to India.

The COVID-19 pandemic highlighted the importance of this partnership, as India shipped millions of doses of vaccines to Brazil under the "Vaccine Maitri" initiative. This cooperation not only strengthened the ties between the two nations but also positioned India as a global leader in public health.

During the pandemic, India exported vaccines and critical medicines to South Africa, Brazil, and Russia, demonstrating the spirit of cooperation enshrined within BRICS. This gesture not only underscored India's capabilities in pharmaceutical manufacturing but also solidified its role as a reliable partner within BRICS. The pharmaceuticals sector remains a crucial area where India and its BRICS counterparts can further strengthen ties, particularly in terms of research, development, and regulatory cooperation.

Challenges and Opportunities

While the economic relations within BRICS hold great potential, they are not without challenges. Trade imbalances, particularly between India and China, remain a concern. Moreover, the varying levels of economic development within BRICS make it difficult to establish uniform policies that benefit all members equally. Geopolitical tensions, particularly involving China, also pose a risk to the long-term stability of BRICS.

However, these challenges also present opportunities. BRICS nations, including India, have recognised the importance of economic diversification and the need to move beyond traditional trade frameworks. There is a growing emphasis on sustainable development, innovation, and technological exchange—areas where India can play a leading role.

As BRICS looks to expand its influence in global governance, India's ability to collaborate with its partners on issues ranging from climate change to digital innovation will be critical. The establishment of the NDB has already demonstrated that BRICS can chart its own course, independent of Western financial institutions, and India will

likely continue to champion such initiatives.

Towards a Shared Future: The Role of Family and Cooperation

It is said that "family is the cornerstone of society," and in many ways, BRICS nations function like a global family, working together towards shared goals of development and progress. This year, celebrated as the "Year of the Family" within BRICS, further emphasizes the values of cooperation, trust, and collective well-being that drive this unique partnership. Just as in a family, the success of one member within BRICS is a triumph for the entire group, making their collaboration even more impactful.

The cooperation within BRICS, especially in trade and economic relations, stands as a testament to what can be achieved when nations come together with a common vision. The breadth of collaboration — from pharmaceuticals to space exploration to cybersecurity — showcases the versatility and depth of their engagement. This cooperation is not only beneficial to BRICS nations but also sets a precedent for multilateralism in the 21st century.

Conclusion

The BRICS framework, in its multilateral dialogues, represents more than just an economic alliance—it embodies a shared vision for the future, rooted in cooperation, mutual respect, and a desire for sustainable development. India, with its growing economic and diplomatic influence, is well-positioned to deepen its relationships within BRICS, particularly in sectors such as pharmaceuticals, space exploration, and cybersecurity.

As the world navigates the complexities of the 21st century, BRICS nations must continue to adapt and innovate, working together on shared values, collective progress, and mutual trust will only grow stronger. This is, after all, the year of the family, and the BRICS nations, as a global family, have shown that together, they can achieve great heights in trade, technology, and beyond. This year, being the "Year of Family", serves as a poignant reminder that unity and cooperation remain at the heart of BRICS' mission, not only in trade relations but in fostering a shared sense of global community.



President Putin's vision behind BRICS' evolution into solid foundation of new world order



Vinay Shukla

Independent Eurasia Analyst

The term was originally coined in 2001 as "BRIC" by the Goldman Sachs economist Jim O'Neill in his report, Building Better Global Economic BRICs. But the credit for its coming to age goes to vision of Russian President Vladimir Putin when foreign ministers of Brazil, Russia, India and China met in Yekaterinburg in May 2008 for their first formal meeting and later leaders of these countries gathered in the same city on the geographical borders of Europe and Asia in June 2009. Later in 2010, South Africa was invited to join the group making it BRICS.

Although over the years all the member states during their presidencies advanced the cause of making BRICS as an influential organization of global politics and providing an alternate view to G7 monopoly in global affairs, but Yekaterinburg summit was the solemn beginning of the formation of a new multi-polar world order based on a solid foundation of the common aspirations of a larger part of humankind.

From the first summit in Yekaterinburg to the upcoming 16th summit in Kazan BRICS has transformed into BRICS+ with the invitation of Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia and the United Arab Emirates at

its last summit Johannesburg last year. More countries have applied for membership or shown interest in joining the BRICS+. However, this issue would have to be decided on the basis of consensus after criteria for eligibility are finalised. After all, envisioned as the club of fastest developing economies, initial members of BRICS complement each other - Russia, Brazil, South Africa have huge natural resources and technological capability, while China and India are major consumers of energy and natural resources with strong manufacturing base and human resources.

Initially, there were voices of scepticism in India, about the prospects of BRIC as a viable construct. However, due to the financial crisis of 2008, which led to formation of G20 as the US-led G7 alone were unable to resolve the financial crisis in the globalised world. Thanks to the highest level of trust between Moscow and New Delhi, the government of prime minister Manmohan Singh decided to join President Putin's initiative to formalise BRIC. With the change of government in New Delhi 2014 after elections many considered Prime Minister Narendra Modi as pro-American and expected him

to walk out of BRICS where China and Russia are leading forces. But as the time showed Prime Minister Modi was only an Indian nationalist and cared only for India's national interests. In spite of furious debates among the rival political parties during the campaign for the parliamentary elections. There is a broad consensus on foreign policy.

Under the leadership of Prime Minister Modi, India has been consistently supporting the cause of development of BRICS and has been actively participating in the developmental work under the current Russian presidency. During his July visit to Moscow and talks with President Vladimir Putin, PM Modi among multilateral issues in detail discussed India's vision to make a robust international tool for economic and trade between the countries of the global south. Meanwhile sherpas of the BRICS+ countries are at work to set the political, economic, trade agenda for their principals to be adopted at the Kazan summit in October to launch a steady movement towards a new world order for the prosperity of the majority of humankind.

Посвящается Нарендре Моду...

Свободен Бхарат и велик,
Сплотил он всех своих сынов,
Идёт он к славе напрямик,
Живет без гнёта и оков.

И Бог рукой Нарендры Моды
Ведёт страну стремительно вперёд.
Воспитан лидер был в народе,
Теперь народ за ним идёт.

Провёл он годы в ашрамах далеких
Искал он истину везде, всегда.
Теперь же к истине ведёт он многих,
И не отступит никогда.

Нарендра Моды, славен будь.
Веди к победе тех, кто предоставил
Тебе на век свою судьбу,
Так чтобы Индию ты навсегда прославил

You are the leader of Indian nation
You are the guiding star for both,
For old and for young generations,
For all who gives the sacred oath
Of loyalty to Bharat and its laws,
The promise to fix all the possible flaws

You make Bharat beautiful and rich,
In hearts of people you light flame,
And all in the world are bewitched
By Indian beauty and fame..



Тимофеев Марк Иванович,

15 лет

Горчаковский Лицей МГИМО

Locating BRICS in the Global Order: Perspectives from the Global South (Book Review)



Ashish Singh

Social and political scientist

“Locating BRICS in the Global Order: Perspectives from the Global South” is an edited volume by Rajan Kumar (Associate Professor, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India), Meeta Keswani Mehra (Professor, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India), G. Venkat Raman (Professor, Indian Institute of Management, Indore, India) and Meenakshi Sundriyal (Assistant Professor, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India). The book came at a time when the importance of BRICS has once again been highlighted. The formation of BRICS was seen as a step towards ensuring multi-polarity. BRICS is the acronym for a group of countries: Brazil, Russia, India, China and South Africa. With time, several other member states have been included into the group, and there are talks of expanding it into a BRICS+ format as well. This intergovernmental group formed to operate in parallel with the Western financial supremacy has a high status for its members.

The book is divided into three parts: Locating BRICS into the Global Order; Member States and their Interests in BRICS; and, New Vistas of Cooperation within BRICS: Lacunae and Possibilities. The introductory chapter moves further from explaining the acronym itself. The idea of BRICS, despite its economic roots, is not limited to despicit matters, but is an attempt towards multilateralism (‘contested multilateralism’). Such multilateralism is distinct and authors optimistically praise BRICS for having “demonstrated a capacity to institutionalise, learned to make consensual decisions, successfully executed policies, and endured border conflicts between two of its prime members.” BRICS emerged at a time when the Western economies were facing financial crisis, therefore, it became obvious for the authors to feel proud in praising BRICS achievements.

The first part as the title suggests introduces the emergence of BRICS in the current Liberal International Order (LIO). This part has seven chapters. The first chapter deals with how the US-led LIO has been created and followed since the end of the Second World War. Comparatively

BRICS is a novel, less institutionalised and informal multilateral platform. The relationship of BRICS member states Russia and China with the US has worsened in the last few years, whereas with India it is improving. Thus, there is a competitive and cross-pressures visibly influencing the functioning of the BRICS. Furthermore, the tensions between India-China over their borders have also put BRICS members into a tough spot. There are vivid discussions about the weaknesses and discontents of the Liberal International Order in this section. It is established that although there is a visible competition between the LIO and the BRICS member states, the latter’s resistance is not against the basic premise of global capitalism, but against the rules and institutions governing them. By giving examples, Rohan (2023) in his essay reiterates that the survival of BRICS also depends on revisiting the member-states’ maritime efforts. Here India should take the lead. Keswani Mehra and Azharuddin (2023) use a data-driven method to showcase the growth, trade and investment trends in BRICS. Those interested in understanding how a differently institutionalised semi-formal group of countries are managing their economic relations must read this essay.

The second part of this volume comprises chapters on five key members of BRICS to present their interests in BRICS. De Conti et al (2023) glean through the case of Brazil in this context. They assert that Brazil has a few challenges in its relations with BRICS. First and foremost is the disequilibrium within BRICS due to the economic and political power China holds. Even though the creation of institutions such as the New Development Bank (NDB) shows BRICS’ commitment to the principle of equal votes, authors argue that it is undeniable that Chinese influence cannot be overlooked. Secondly, the trade trends of Brazil show “the possibility of Brazil changing the structure of its external trade in favour of higher valued-added goods will probably not be reached within BRICS. To the contrary, trade with BRICS countries tends to reinforce Brazil’s position in the interna-

tional division of labour, as a supplier of mineral and agricultural commodities.” Brazil faces another challenge vis-à-vis BRICS due to the changes taking place in its domestic politics. Kharitonova (2023) presents the case of Russia in this context. While highlighting several key issues, Kharitonova successfully affirms that for Russia, BRICS is ‘the partnership in the interests of global stability, mutual security and innovation growth’. Kumar (2023) attempts to decipher India’s role in BRICS, however, this chapter at times gives the impression of an essay on Indian supremacy within BRICS. The essay by Zongyi (2023) about China and BRICS is realistic in assessing the role of China as well as the dynamics within BRICS due to changing global dynamics.

The section consists of essays to emphasise on the possibilities and challenges BRICS faces based on its recent experiences. Two chapters describe how BRICS countries dealt with the Covid-19 pandemic, how their strategies were different due to internal political structures, their healthcare systems and demography. In doing so, these chapters also showcase where can be the possibilities of future cooperation among the member countries. Additionally, they also highlight the limitations BRICS has faced due to limited cooperation among its members. The chapter on BRICS and development aid is useful for those trying to understand multilateral cooperation in the humanitarian sector.

In conclusion, it can be said that the book is a collection of a few good essays highlighting the background, journey, challenges and possibilities of BRICS. The introductory chapter hints of optimism, however, as the readers dive into the volume, they find that ground realities are also dealt with in several essays, using critical realism.

Rajan Kumar, Meeta Keswani Mehra, G. Venkat Raman and Meenakshi Sundriyal (eds.), *Locating BRICS in the Global Order: Perspectives from the Global South* (London and New York: Routledge, 2023), pp. xix + 337, £39.99. ISBN 9780367708085 (Paperback).

India in the Arctic: Past, Present, and Future



Vichare Aniket Sachin

International Master program CORELIS —
Cold Region Landscapes Integrated Sciences
St. Petersburg State University

India's journey into the Arctic symbolises its expanding scientific aspirations and geopolitical ambitions. Over the years, India has transitioned from establishing its first research base in Svalbard to formulating a comprehensive Arctic policy, making notable strides in polar research. This narrative delves into India's past endeavours, current initiatives, and anticipated future role in the Arctic, while also considering the involvement of BRICS nations in this dynamic region.

India's polar research initiatives commenced with the establishment of the National Centre for Polar and Ocean Research (NCPOR) on May 25, 1998. Initially focused on Antarctica, NCPOR broadened its horizons to include Arctic research in 2008 by setting up the "Himadri" research base in Svalbard. This strategic move marked India's formal entry into Arctic research, facilitating annual summer expeditions and culminating in its first winter expedition in 2023.

In March 2022, India unveiled its Arctic policy titled "India and the Arctic: Building a Partnership for Sustainable Development." This policy outlines six core pillars that guide India's approach to the Arctic: scientific research and cooperation, climate and environmental protection, economic and human development, transportation and connectivity, governance and international cooperation, and national capacity building. These pillars reflect India's commitment to fostering sustainable development while enhancing its scientific presence and engagement in the Arctic region.

A key partner in India's Arctic endeavours is the Arctic and Antarctic Research Institute (AARI) of Russia, which has a rich history in polar research since its establishment in 1920. In April 2024, the director of AARI visited Goa to discuss

potential collaborations with NCPOR, emphasising ongoing cooperation between the two institutes. Future collaborative efforts may include joint research expeditions, the establishment of drifting stations for long-term data collection, and exchange programs for young scientists, enhancing both institutions' research capabilities.

During the upcoming Polar 2024 conference in St. Petersburg in May 2024, the Director of NCPOR emphasised India's keen interest in studying Arctic climate dynamics and their influence on the Indian monsoon. This focus highlights the interconnectedness of global climate systems and underscores India's commitment to understanding how Arctic changes impact weather patterns in South Asia.

Looking ahead, India's role in the Arctic is expected to expand significantly, driven by its scientific ambitions and strategic interests. The Indian scientific community is actively engaged in climate change research, which is vital for understanding global climate patterns and developing mitigation strategies. Additionally, India's Arctic policy emphasises sustainable development, ensuring that economic activities do not compromise the fragile Arctic ecosystem. As an observer in the Arctic Council, India is committed to participating in international governance frameworks that promote peace and cooperation in the region.

Technological advancements are also on the horizon, with India's investment in polar research infrastructure, including plans to acquire its own polar research ship for approximately \$310 million within the next five years. This investment will significantly enhance India's capabilities in Arctic research, enabling more extensive and detailed studies in this crucial region. Collaborations with countries like Russia

will further bolster India's technological expertise in polar exploration.

Moreover, the Northern Sea Route presents substantial economic opportunities for India, particularly regarding trade and energy resources, fostering improved connectivity with other Arctic states. The BRICS nations—Brazil, Russia, India, China, and South Africa—demonstrate varying levels of interest in the Arctic, with Russia being the only Arctic state. The other BRICS countries, including India, hold observer status in the Arctic Council and are increasingly exploring scientific, economic, and geopolitical opportunities in the region. Collaborative efforts among BRICS could focus on shared areas of expertise such as climate change research, marine biology, and geology, utilising the Northern Sea Route for strategic trade benefits.

India's journey in the Arctic is a synthesis of scientific curiosity, strategic interests, and a dedication to sustainable development. With a robust Arctic policy and strong international partnerships, India is well-positioned to play a pivotal role in the Arctic's future. As global attention increasingly turns to this unique and rapidly changing region, India's contributions will be crucial in shaping its trajectory. The involvement of BRICS nations further underscores the importance of international cooperation in addressing the myriad challenges and opportunities the Arctic presents.

In conclusion, India's foray into the Arctic is not just about exploration; it is a proactive engagement with the challenges of climate change, sustainable development, and geopolitical stability. As the Arctic evolves, India's role will likely become increasingly significant, fostering collaboration and innovation in one of the world's most critical regions.

Literature:

India's Arctic Policy, 2022, <https://www.moes.gov.in/sites/default/files/2022-03/compressed-SINGLE-PAGE-ENGLISH.pdf>

Kubny, H. (2023). India is planning its own polar research ship. Retrieved April 2024,

from Polar Journal: <https://polarjournal.ch/en/2023/11/08/india-is-planning-its-own-polar-research-ship/>

Bisen, A. (2023) India's Arctic Endeavours: Capacity Building and Capability Enhancement. Retrieved April 2024,

from The Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses (MP-IDSA) <https://www.idsa.in/policybrief/Indias-Arctic-Endeavours-270723>

Seethi, K.M. (2021) The Contours of India's Arctic Policy, The Arctic Institute <https://www.thearcticinstitute.org/contours-indias-arctic-policy/>

ब्रिक्स उपेक्षा से मान्यता तक

► गौतम कश्यप

(रूसी अनुवादक)

Gautam@Kashyap.ru



ब्रिक्स का गठन 2009 में हुआ था, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। शुरुआत में इस समूह को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था क्योंकि यह समूह अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट नहीं कर पा रहा था। इस कारण इसके महत्व पर प्रश्न उठने लगे थे। पश्चिमी विश्लेषकों द्वारा ब्रिक्स को एक अस्थायी गठबंधन माना जा रहा था, जिसमें स्थिरता और प्रभावशीलता की कमी थी। उनके द्वारा ब्रिक्स के उदय को मुख्य रूप से आर्थिक नजरिये से देखा गया, साथ ही, ब्रिक्स परिवार ने भी खुद को उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ के रूप में प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं और वैश्विक सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना था। हालांकि, हालिया वर्षों में यह संगठन ना सिर्फ वैश्विक अर्थव्यवस्था, बल्कि वैश्विक राजनीति में भी महत्वपूर्ण स्थान बनाने में सफल रहा है, और अब हाल यह है की G7 जैसे संघ इससे भयभीत नजर आ रहे हैं।

2022 में यूक्रेन में नाजीवाद के खिलाफ रूस के विशेष सैन्य अभियान के बाद रूस की आक्रामक विदेश नीति, रूस को चीन का कूटनीतिक और आर्थिक समर्थन, और पश्चिमी प्रतिबंधों के खिलाफ भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे ब्रिक्स सदस्य देशों का रुख तथा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ब्रिक्स के सदस्यों का रूस के खिलाफ वोटिंग में भाग लेने से स्पष्ट इनकार ने ब्रिक्स गठबंधन की महत्वाकांक्षाओं और भू-राजनीतिक वजन को उजागर किया है। इस नई मान्यता ने 2007 के समक्ष एक चुनौती पेश की है, कि अब ब्रिक्स को न केवल एक आर्थिक प्रतियोगी के रूप में, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देने में सक्षम एक भू-राजनीतिक शक्ति के रूप में भी देखना होगा। यही कारण है कि पश्चिमी देशों की आँखों में यह समूह तेजी से खटक रहा है। इसका एक ताजा उदाहरण है, 12 सितंबर, 2024 को, जब भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर के समक्ष जेनेवा में थिंक टैंक 'ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी' में फ्रांस के राजदूत जीन-डेविड लेविटे ने एक सवाल लाया कि आखिर ब्रिक्स की जरूरत ही क्या है? इस पर श्री जयशंकर ने जबाब दिया कि वह ब्रिक्स समूह को लेकर विकसित दुनिया में "असुरक्षा" से आहत हैं। अगर जी-20 के रहते जी-7 का अस्तित्व हो सकता है, तो कोई कारण नहीं है कि ब्रिक्स नामक एक और क्लब का अस्तित्व न हो।

सवाल है कि आखिर ब्रिक्स की जरूरत ही क्या है? 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था समाप्त हो गई। इसके बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा साम्राज्यवादी ताकतों ने लगभग सभी वैश्विक संस्थाओं पर कब्जा जमा लिया तथा उसका इस्तेमाल अपने हितों की पूर्ति तथा अपने नियमों पर आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण करने लगे। ऐसे में ब्रिक्स का निर्माण इस एकाधिकार को तोड़ने और अंतराष्ट्रीय संस्थाओं के लोकतंत्रीकरण की आवश्यकता पर बल देता है। एक संगठन के रूप में ब्रिक्स उन शोषित देशों की आवाज है, जो लंबे समय से पश्चिमी देशों की नीतियों से त्रस्त थे और वर्तमान में भी दबाव का सामना कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि ब्रिक्स में ईरान, मिस्र, इथियोपिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश शामिल हुए और ब्रिक्स प्लस का निर्माण किया। ब्रिक्स प्लस को बनते देख पश्चिमी देशों के कई विश्लेषकों ने इसे एक खतरा के रूप में देखना शुरू कर दिया है, और उनके वैज्ञानिक और शोध आलेख विभिन्न शोध पत्रिकाओं और अखबारों के माध्यम से सामने आ रहे हैं।

रूस पर जिस तरह से पश्चिमी देशों द्वारा आक्रामक आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया, उसके बाद से ब्रिक्स देशों का भरोसा पश्चिमी सहयोगियों से उठ सा गया है। ऐसे में ब्रिक्स में नई मुद्रा लाने और नए बैंक के विकास की बात की जा रही है। यह वक्त की माँग है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका की पक्षपातपूर्ण विदेश नीतियों और ऋण की स्वीकृति में उनके हस्तक्षेप के कारण विकासशील देशों को अक्सर 'अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष और 'अन्तरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक' जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस पक्षपात के कारण ब्रिक्स देशों की कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो सकीं। इसका सीधा मतलब है कि जो देश अमेरिकी राजनीतिक एजेंडे का समर्थन करेंगे, उन्हें आसानी से ऋण मिल जाएगा, जबकि अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा के लिए जो भी देश पश्चिमी तानाशाही का विरोध करेंगे, उनके सामने समस्याएं पैदा की जायेंगी और उन्हें अमेरिका की कठपुतली बनने को मजबूर किया जाएगा।

भारत ने पहली बार 2012 में दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली के मुद्दे को उठाया था, जिसमें तर्क

दिया गया था कि इससे न केवल ब्रिक्स देशों को बल्कि सभी विकासशील और अविकसित देशों को लाभ होगा। 2014 में ब्रिक्स ने 100 अरब डॉलर की शुरुआती अधिकृत पूंजी के साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक का शुरुआत किया, लेकिन इसमें एक समस्या थी कि बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण इसपर चीन का एकाधिकार होने का डर था। ऐसे में यह परियोजना दुलमुल गति से काम कर रही थी। अब चूंकि नई विश्व व्यवस्था में अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के एकाधिकार को चुनौती देने और डॉलर पर निर्भरता को कम करने के लिए लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है, ऐसे में ब्रिक्स देशों के बीच परस्पर सम्मान और विश्वास की बहाली का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर ब्रिक्स एक नई वैश्विक व्यवस्था का निर्माण करना चाहता है, जो उसकी जरूरत भी है, तो उसके लिए सदस्य देशों के बीच आपसी विवादों का सुलझाया जाना अत्यंत जरूरी है, वरना यह किसी दिन पूरे ब्रिक्स के उद्देश्यों का तबाह कर सहती है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) की असफलता से इस बात को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। ब्रिक्स की सफलता के लिए सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में ही सहयोग काफी नहीं है। इसका इस्तेमाल दुनिया की आधी आबादी के बीच सांस्कृतिक और नैतिक आदान-प्रदान के लिए भी की जानी चाहिए। महात्मा गांधी का प्सर्वोदयः सिद्धांत, जिसमें समाज के सभी वर्गों के कल्याण की बात है, ब्रिक्स देशों के लिए मार्गदर्शक हो सकता है।

देखा जाए तो ब्रिक्स की यात्रा उपेक्षा से मान्यता तक एक प्रेरणादायक कहानी है। वैश्विक बदलाव के प्रतीक के रूप में इस मंच ने साबित किया है कि साम्राज्यवादी ताकतों के विरुद्ध किस तरह उभरती अर्थव्यवस्थाएं अपनी पहचान को बनाये रखते हुए वैश्विक मंचों पर प्रभावी हो सकती हैं तथा अपने सामूहिक हितों के लिए मिलकर काम कर सकती हैं। वैश्विक राजनीति में ब्रिक्स की आर्थिक और राजनीतिक ताकत पश्चिमी देशों को परेशान कर रही है, जिससे पता चलता है कि ब्रिक्स सफलता की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत और उनका 'स्वराज' का विचार, जो आत्मनिर्भरता और सामूहिक सहयोग पर आधारित है, ब्रिक्स का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

महात्मा गांधी जी ने दुनिया को सदा के लिए कैसे बदल दिया ?

► वरवरा शेरबकोवा

छात्रा – द्वितीय वर्ष,
रूसी राजकीय मानविकी विश्वविद्यालय



महात्मा गांधी जी को पूरी दुनिया में एक महान व्यक्ति माना जाता है। उन्होंने न केवल भारतीय लोगों को अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई में आशा और विश्वास दिया, बल्कि उनके अहिंसा के दर्शन ने संसार भर के लोगों को प्रभावित किया। आधुनिक दुनिया लगातार नई चुनौतियों और संघर्षों का सामना कर रही है, ऐसे में उनके विचार और सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं।

बचपन से ही गांधी जी ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत अपने लोगों के साथ होने वाले अन्याय और उत्पीड़न को देखा था। वे सदा कहते थे, **“खुद वह बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं,”** और यही सिद्धांत उनके जीवन पथ का आधार बन गया। भारत की आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी जी ने प्रतिरोध का अहिंसक तरीका अपनाया। उनका प्रसिद्ध उद्धरण **“आँख के**

बदले आँख पूरे विश्व को अंधा बना देगी” शांतिपूर्ण प्रतिरोध के महत्व पर जोर देता है।

इन सिद्धांतों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे नागरिक अधिकार आंदोलन के नेताओं को भी बहुत प्रभावित किया। हालांकि गांधी जी के कुछ आलोचकों का तर्क था कि उनके स्वतंत्रता संग्राम के तरीके बहुत निष्क्रिय थे और शीघ्र परिणाम नहीं दे सकते थे। वे मानते थे कि कट्टरपंथी और मजबूत कार्रवाई से भारत को जल्दी मुक्ति मिल सकती है, लेकिन गांधी जी का विश्वास यही था कि केवल अहिंसा ही देश में वास्तविक परिवर्तन ला सकती है।

वे कहते थे, **“मुझे केवल एक मार्ग ही मालूम है – अहिंसा का मार्ग। हिंसा का मार्ग मेरी प्रकृति के विरुद्ध है। मैं हिंसा का पाठ पढ़ाने वाली शक्ति को बढ़ाना नहीं चाहता...**

” उनकी यह बात पूरी दुनिया में गूंज गई। अंत में, मैं यह कहना चाहती हूँ कि महात्मा गांधी जी की विरासत का दुनिया पर गहरा प्रभाव बना रहा है, क्योंकि हम अभी भी हिंसा, युद्ध, पर्यावरणीय समस्याओं आदि का सामना कर रहे हैं। उनका जीवन, भारत की स्वतंत्रता के लिए उनका संघर्ष और अहिंसक प्रतिरोध का दर्शन, उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है जो शांति, स्वतंत्रता और न्याय के लिए दुनिया भर में प्रयासरत हैं। आधुनिक दुनिया में गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता स्पष्ट है, क्योंकि उन्होंने वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए अहिंसक, आध्यात्मिक और नैतिक तरीके प्रस्तुत किए।

मेरा मानना है कि गांधी जी की विरासत मानवता को पूर्णता और सद्भाव की ओर प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहेगी।

महात्मा गांधी : अहिंसा की स्थायी विरासत

► आलेसिया सवेलियेवा,
मस्कवा



“भारत के राष्ट्रपिता” के रूप में जाने जाने वाले महात्मा गांधी ने विश्व इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। अहिंसा और शांतिपूर्ण प्रतिरोध के उनके दर्शन ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, बल्कि दुनिया भर के लाखों लोगों को न्याय और समानता के लिए लड़ने हेतु प्रेरित किया।

गांधी जी का जीवन स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के संघर्ष के लिए समर्पित था। उनका सत्याग्रह या प्रतिरोध का अहिंसक तरीका सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण था। 1930 का नमक मार्च, जब गांधी जी ने ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया, शांतिपूर्ण विरोध की ताकत का एक शक्तिशाली उदाहरण था। सविनय अवज्ञा का यह कार्य लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी का प्रभाव भारत से कहीं आगे फैला हुआ था। उनके विचारों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग

जूनियर और दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं को प्रेरित किया। किंग ने अफ्रीकी-अमेरिकियों के नागरिक अधिकारों की लड़ाई में अहिंसक प्रतिरोध के सिद्धांतों को अपनाया, और मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ लड़ाई में गांधी के दर्शन का इस्तेमाल किया। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति का विचार पूरे समाज को बदल सकता है।

संघर्ष और हिंसा से भरी आज की दुनिया में, गांधी की शिक्षाएँ पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक बनी हुई हैं। उनके अहिंसा और पारस्परिक सम्मान के सिद्धांत सामाजिक अन्याय, राजनीतिक ध्रुवीकरण, और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्याओं को हल करने का एक वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत करते हैं। गांधी जी ने सिखाया कि वास्तविक परिवर्तन हममें से प्रत्येक के साथ शुरू होता है। उन्होंने लोगों को चुनौती देते हुए कहा, **“आप स्वयं वह परिवर्तन बनें जिसे आप दुनिया में देखना चाहते हैं।”**

गांधी जी की सादगी, ईमानदारी और

करुणा के आध्यात्मिक सिद्धांत आधुनिक समाज में बढ़ते भौतिकवाद और व्यक्तिवाद को भी संतुलन प्रदान करता है। उनका संदेश कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास में निहित है, उपभोक्तावाद के इस युग में एक शक्तिशाली संदेश बना हुआ है।

निष्कर्षतः, यह कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी की विरासत आज भी जीवित है और नई पीढ़ियों को प्रेरित कर रही है। उनका जीवन एवं उनकी शिक्षाएँ यह स्पष्ट करती हैं कि शांतिपूर्ण तरीके सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन प्राप्त करने के प्रभावी उपकरण हो सकते हैं। ऐसी दुनिया, जहाँ अक्सर हिंसा ही एकमात्र समाधान लगती है, गांधी जी का दर्शन हमें अहिंसा, करुणा और मानवीय गरिमा की शक्ति की याद दिलाता है। दुनिया पर उनका प्रभाव स्थायी बना हुआ है, जो उन लोगों को आशा और मार्गदर्शन प्रदान करता है, जो न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए प्रयासरत हैं।

जानवरों के प्रति नैतिकता : महात्मा गांधी के विचारों की वैश्विक प्रासंगिकता

► मार्गरीटा एर्माल्युक

छात्रा – द्वितीय वर्ष,
रूसी राजकीय मानविकी विश्वविद्यालय



“एक देश की महानता और नैतिक प्रगति को इस बात से आँका जा सकता है कि वहाँ जानवरों से कैसे व्यवहार किया जाता है।”
— महात्मा गांधी

मैं महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक सिद्धांतों के बारे में बात करना चाहती हूँ। गांधी जी के इस अनमोल विचार को पढ़ने के बाद मैं सोचने लगी कि यह सच है, क्योंकि दुनिया भर में पशु संरक्षण के कानून अब भी पूरी तरह से प्रभावी नहीं हैं। यदि लोग दूसरों की पीड़ा को कम करने के साथ-साथ पशु-पक्षियों की रक्षा करते और उन्हें नहीं मारते, तो यह वास्तव में एक सभ्य समाज का प्रतीक होता।

विश्वभर में जानवरों और उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों के बारे में पढ़ते हुए, मेरी नजर चीन में पशु अधिकारों के लिए चल रही लड़ाई पर पड़ी। चीन की बढ़ती समृद्धि के साथ

वहाँ पशु उत्पादों की माँग भी बढ़ रही है। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कुछ जानवरों को जिंदा ही चमड़ी से अलग किया जा रहा था और उन्हें अन्य मरे हुए जानवरों के ढेर में फेंक दिया जा रहा था, जहाँ वे धीरे-धीरे मर रहे थे।

यह सोचकर बहुत दुख होता है कि लोग प्राचीन सभ्यताओं की परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी के एक चीनी दार्शनिक ने कहा था कि “प्रेम न केवल मनुष्यों के बीच बल्कि सभी जीवित प्राणियों के बीच होना चाहिए।” अच्छी बात यह है कि आज चीन में पशु अधिकारों के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ता हैं, जिनके संदेश को लोग अब सुनने लगे हैं। पहले लोगों को चीनी चिड़ियाघर आकर्षित करते थे, जहाँ वे मुर्गियों, बकरियों, और घोड़ों को खरीदकर शेरों, बाघों, और अन्य बड़ी बिल्लियों के सामने फेंक देते, ताकि वे उनके टुकड़े-टुकड़े होते देख सकें। अब चीनी सरकार

ने सरकारी चिड़ियाघरों में इस तरह की क्रूरता पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन, निजी चिड़ियाघरों और सर्कस में जानवरों के साथ क्रूरता के मामले अभी भी मिलते हैं। हालाँकि, चिड़ियाघरों और सर्कसों में तकलीफ झेलने वाले जानवरों की संख्या औद्योगिक पशु उत्पादन के कारण पीड़ित जानवरों की तुलना में काफी कम है।

इस उदाहरण से मैं यह कहना चाहती हूँ कि महात्मा गांधी जी ने दुनिया को हमेशा के लिए क्यों बदल दिया। इस निबंध के माध्यम से मैं सभी को बापू जी के अहिंसा के दर्शन की याद दिलाना चाहती हूँ। उनका विचार कि “एक देश की महानता और नैतिक प्रगति को इस बात से आँका जा सकता है कि वहाँ जानवरों से कैसे व्यवहार किया जाता है” आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था।

गांधी और उनके आध्यात्मिक सिद्धांत

► एलिना ज्य्यागिन्त्सेवा

छात्रा – द्वितीय वर्ष,
रूसी राजकीय मानविकी विश्वविद्यालय



महात्मा गांधी आधुनिकता के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक थे और भारत के आध्यात्मिक नेता माने जाते हैं। उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और उन्हें न केवल भारत में, बल्कि विदेशों में भी व्यापक सम्मान प्राप्त है।

गांधी जी ने अनेक रचनाएँ लिखीं, जिनमें उन्होंने विभिन्न मूल्यों का वर्णन किया है। उनकी आत्मकथा “मेरा जीवन” और दर्शन को दर्शाने वाली किताब “सत्य के प्रयोग” उनके विचारों और जीवन के मार्ग का परिचय देती हैं। गांधी जी विश्व नेताओं में एक अद्वितीय नेता रहे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अनोखे तरीके अपनाए। उनकी राजनीतिक गतिविधियाँ दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुईं, जहाँ उन्होंने कठोर निर्णय लेने की कला सीखी। कई बार उन्हें धन अर्जित करने का अवसर मिला, फिर भी उन्होंने साधारण जीवन जीने का संकल्प लिया और धन से दूर रहे।

गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे, जो हर परिस्थिति में अपने सिद्धांतों के प्रति वफादार

रहे। जब वे गंभीर चुनौतियों में फँसे, तब भी उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और अंततः विजयी हुए। महात्मा गांधी ने अपने आपको सफल वक्ता नहीं माना, लेकिन उन्होंने नेतृत्व के अनेक सिद्धांत बनाए, जिनका वे स्वयं पालन करते थे। भारतीय लोग उन्हें बापू के रूप में मानते थे, जिसका कारण यह था कि महात्मा ने अपने सत्याग्रही प्रयासों पर कभी संदेह नहीं किया।

गांधी जी ने दो मूल्यों को अपनाया: अहिंसा और सत्य। ये दोनों अवधारणाएँ आपस में जुड़ी हुई हैं। उनका कहना था, “आपको सत्य का पालन करना चाहिए, जो आपको मुक्ति प्रदान करेगा।”

मैंने गांधी जी के जीवन की कहानी रूसी में पढ़ी और उनके साहस से प्रभावित हुई हूँ। वास्तव में, वे एक बहादुर व्यक्ति थे, जिन्हें राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ बोलने में डर नहीं लगता था। मुझे पता चला कि दक्षिण अफ्रीका में सभी भारतीयों को “कुली” कहा जाता

था और गांधी को “कुली वकील” के नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी आत्मा को तब पीड़ा होती थी जब वे देखते थे कि भारतीय लोग भूख से मर रहे हैं। उन्होंने लोगों को भूख के खिलाफ अहिंसक संघर्ष सिखाया, जो बाद में ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्ति का आंदोलन बन गया।

भारतीय और रूसी संस्कृति में कई समानताएँ हैं, जो गांधी और लेफ तलस्तोय जैसे दो महान लोगों के विचारों को एकमत साबित करती हैं। गांधी ने कहा कि महान रूसी लेखक ने बुराई के खिलाफ लड़ाई में उनके विश्वास को मजबूत किया। गांधी जी लेफ तलस्तोय के विचारों, जैसे कि अहिंसा, कार्यशीलता, और आत्म-नियंत्रण से प्रभावित हुए, जो हिन्दू धर्म के मूल सिद्धांतों के अनुकूल हैं। इनमें अहिंसा, सविनय अवज्ञा, यज्ञ (कार्य) और योगाभ्यास शामिल हैं, जो आत्मा और शरीर को नियंत्रित करते हैं। गांधी स्वयं मानते थे कि उनके जीवन का उद्देश्य सत्य की सेवा करना है।

रुस में हिन्दी की लोकप्रियता

► डॉ. इंदिरा गाजिएवा,
प्राध्यापिका
रुसी राजकीय मानविकी विश्वविद्यालय



रुस में हिन्दी भाषा के प्रति लोगों के आकर्षण का मुख्य कारण भारतीय संस्कृति को करीब से जानने की चाहत है। एक और कारण यह भी है कि रुस में 15,000 से भी अधिक भारतीय रहते हैं, जो सालभर रुसियों के साथ मिलकर होली, दिवाली, दुर्गापूजा, ईद आदि प्रमुख त्योहार बड़े उत्साह और धूम-धाम से मनाते हैं। रुसी लोग भी भारतीय संस्कृति और रीति-रिवाजों से जुड़ने की गहरी इच्छा रखते हैं।

रुस में जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र और भारतीय दूतावास के माध्यम से हिन्दी काव्यापक प्रचार-प्रसार होता है। डॉ० मीनू शर्मा जी इस सांस्कृतिक केंद्र में प्राध्यापिका के रूप में हिन्दी भाषा का प्रसार करती हैं। डॉ० शर्मा स्वयं एक कवयित्री हैं और उन्होंने देशभक्ति, प्रेम, मित्रता, और माता-पिता जैसे विषयों पर कई कविताएँ लिखी हैं। आजकल वह रुसी

विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को हिन्दी की वरिष्ठ कथाकार चित्रा मुद्गल की रचनाओं से परिचित करा रही हैं, जिन्हें छात्र हिन्दी से रुसी भाषा में अनूदित करने का प्रयास कर रहे हैं।

रुस में लम्बे समय से हिन्दी भाषा के प्रति गहरी दिलचस्पी रही है। वर्तमान में, रुस के छह विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जाती है, और रुसी छात्र इसे गहराई से समझना चाहते हैं। वे हिन्दी कवियों की रचनाएँ पढ़ते हैं और उनका अनुवाद रुसी भाषा में करते हैं।

मस्क्वा स्थित रुसी राजकीय मानविकी विश्वविद्यालय में हर साल हिन्दी महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें ढेरों विविधतापूर्ण कार्यक्रम होते हैं। प्रमुख विद्वान विद्यार्थियों को अपने अनुसंधानों से परिचित कराते हैं तथा संस्कृति, मानवविज्ञान, धर्म, और भारतीय राजनीतिक जीवन से संबंधित जानकारी साझा करते हैं।

डॉ. रामेश्वरसिंह, जो मस्क्वा स्थित रुस-भारत मैत्री संघ 'दिशा' के निदेशक हैं, नियमित तौर पर मस्क्वा विश्वविद्यालय और रुसी राजकीय मानविकी विश्वविद्यालय में हिन्दी भाषा से संबंधित संगोष्ठियों का आयोजन करते रहते हैं। इसके अलावा, 'दिशा' पत्रिका के माध्यम से वे पूरे रुस में हिन्दी अध्ययन का प्रचार-प्रसार करते हैं।

'हिन्दुस्तानी समाज', भारतीय संघ के नेतृत्व में, सालाना रुसी छात्रों के बीच हिन्दी-रुसी अनुवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप रुसी छात्रों को उत्कृष्ट अनुवाद के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

हम सभी हिन्दी प्रेमी हैं और रुसी लोगों के बीच इस अद्भुत भाषा को फैलाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं।



क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द
ध न प फ ब भ म य र ल व श ष स ह क्ष त्र ज्ञ

क ख ग 

Disha Ramlila Revives the Legacy of Russian-Indian Friendship at Ayodhya's Deepotsava 2023

In a remarkable celebration of cultural unity, the Russian-Indian Friendship Society "DISHA" presented the play "Disha Ramlila" during the grand Deepotsava (Diwali) festival in Ayodhya, Uttar Pradesh, from November 9-11, 2023. Organized by the Ayodhya Research Institute (Ayodhya Shodh Sansthan) and held under the patronage of Hon'ble Chief Minister of Uttar Pradesh, Mr. Yogi Adityanath, the event honored both Indian mythology and the enduring ties between India and Russia.

The Ramayana, one of India's most revered ancient epics, tells the timeless story of Lord Rama's journey of righteousness, exile, and ultimate return to Ayodhya after defeating the demon king Ravana. The Ramcharitmanas, written by the 16th-century poet Tulsidas, is a retelling of this epic in Awadhi, a dialect of Hindi, and has played a pivotal role in shaping the cultural fabric of North India. Ramlila, the dramatic enactment of the Ramayana, brings this revered tale to life through performances that depict Lord Rama's journey, embodying moral and ethical values cherished in Indian culture.

The history of Ramlila in Russia dates back to the 1960s, largely due to the efforts of Gennady Mikhailovich Pechnikov, a Soviet actor, theater director, and public figure, who earned the affectionate title "Russian-Rama" for his dedication to staging this classic Indian

performance. Pechnikov's Ramlila was not only a celebration of the epic but also a symbol of the cultural bridges between Russia and India. He performed the play across India and Russia, receiving numerous accolades, including the Padma Shri and the Bal Mitra Award.

In honor of Pechnikov's legacy and Russian-Indian friendship, the Russian-Indian Friendship Society "DISHA" revived the production of Disha Ramlila in 2018, with its first performance in Ayodhya. Following successful presentations at Prayagraj's Kumbh Mela in 2019 and Ayodhya's Deepotsava in 2022, the 2023 performance continued this cherished tradition. Artists from various countries were invited to perform at this year's Deepotsava, with Disha Ramlila standing out for its portrayal of the mythological saga.

Dr. Rameshwar Singh, President of DISHA, expressed his heartfelt gratitude to Hon'ble Chief Minister Yogi Adityanath for inviting DISHA to represent Russia once again. He emphasized the importance of celebrating Lord Rama's return to Ayodhya and the deepening cultural bonds between the two nations, further enriching the shared heritage through art and performance.

ДИША Рамлила памяти Падма Шри Г.М. Печникова
पद्मश्री गेनादी पेचनीकोव स्मृति 'दिशा' रामलीला मास्को, रूस
Padma Shri Genadi Pechnikov Memorial Disha Ramleela



Dr. Rameshwar Singh
Producer & Director
+7 985 341 38 59 (Moscow)

Рамлила «Диша» возрождает наследие российско-индийской дружбы на Дипотсаве 2023 в Айодхье

В рамках яркого празднования культурного единства Общество российско-индийской дружбы «Диша» представило спектакль «Диша Рамлила» на грандиозном фестивале Дипотсава (Дивали), который прошел в Айодхье, штат Уттар-Прадеш, с 9 по 11 ноября 2023 года. Мероприятие было организовано Институтом исследований Айодхьи (Айодхья Шодх Санстхан) при поддержке главного министра Уттар-Прадеша, почтенного господина Йоги Адитьяната. Этот праздник почтит как индийскую мифологию, так и прочные культурные связи между Индией и Россией.

Рамаяна — одно из самых почитаемых древних эпических произведений Индии, рассказывающее о пути праведности Господа Рамы, его изгнании и триумфальном возвращении в Айодхью после победы над демоническим царем Раваной. Рамчаритманас, написанная в XVI веке поэтом Тулсидасом, является пересказом этого эпоса на языке Авадхи и сыграла важную роль в формировании культурного наследия северной Индии. Рамлила, театральное воплощение Рамаяны, оживляет этот священный эпос через драматические постановки, отражающие путь Господа Рамы и воплощающие важные моральные и этические ценности индийской культуры.

История Рамлилы в России началась в 1960-х годах благодаря усилиям Геннадия Михайловича Печникова, советского актера, театрального режиссера и общественного деятеля, который

получил прозвище «Русский Рама» за свою приверженность постановке этого классического индийского спектакля. Постановки Печникова Рамлилы не только прославляли индийский эпос, но и служили символом культурных мостов между Россией и Индией. За свою деятельность Печников получил множество наград, в том числе Падма Шри и медаль «Бал Митра».

В честь наследия Печникова и российско-индийской дружбы Общество «Диша» возродило постановку Диша Рамлилы в 2018 году, первая презентация которой прошла в Айодхье. Успешные выступления также состоялись на Кумбх Меле в Праяградже в 2019 году и на Дипотсаве в Айодхье в 2022 году. Постановка 2023 года продолжила эту ценную традицию. В этом году на Дипотсаву были приглашены артисты из разных стран, но Диша Рамлила особенно выделялась своей интерпретацией мифологического эпоса.

Президент общества «Диша» доктор Рамешвар Сингх выразил искреннюю благодарность почтенному главному министру господину Йоги Адитьянату за приглашение вновь представить Россию на этом мероприятии. Он подчеркнул важность празднования возвращения Господа Рамы в Айодхью и укрепления культурных связей между двумя странами, которые продолжают обогащать общее наследие через искусство и театральные постановки.



Disha Ramlila Depotsav Ayodhya 2017-2023



«Пища жизни» - благая миссия для детей и для довольства Бога



Юлия Нуриевна Абдрафизин
(Журналист и редактор)

Володарский район, Нижегородская область

Движение «Пища жизни» существует со времён Шрилы Прабхупады, он дал старт этой благой миссии на фоне Сознания Кришны, и он же дал название этому движению. Последователи Шрилы Прабхупады теперь есть по всему миру, и вместе с ними активно распространяется движение, участники которого распространяют прасад среди тех слоев населения, где запрос на еду особенно актуален. В Нижнем Новгороде движение «Пища жизни» приобрело особую активность и популярность с началом пандемии, когда детей перевели на дистанционное обучение и тема еды стала особенно актуальной в многодетных и малообеспеченных семьях. О движении «Пища жизни» рассказал его куратор в Нижнем Новгороде Сита Путра прабху:

«В рамках этого движения распространяется прасад, а прасад даёт пищу не только телу, но и душе. Прасад готовится из того, что выросло из земли, а в земле есть остатки умерших животных, растений, и то, что выросло из земли несет отпечаток прошлых жизней этих существ, их кармы. А когда мы предлагаем эту пищу Господу, мы очищаем её от прошлой кармы и плохой энергетики. Когда мы искренне предлагаем эту пищу Кришне, она становится чистой. Мы это практикуем всегда.

Само это движение идёт со времён Шрилы Прабхупады, но именно этот, наш коллектив «Пища жизни» Харе Кришна Нижний Новгород возник во время пандемии. В начале пандемии мы обратились к партии «Единая Россия» с идеей помогать таким образом многодетным семьям - бескорыстно, бесплатно кормить детей.

- Помощь была ориентирована именно на многодетные семьи?

- Есть ещё дети неблагополучных родителей-алкоголиков, матерей-одиночек, дети просто бедных родителей. И количество их в таких ситуациях значение не имеет. И многие из таких детей состоят на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних. КДН в районах Нижнего Новгорода стали предоставлять нам списки таких детей, которые потенциально нуждались в нашей помощи. И мы, сотрудничая с партией «Единая Россия», используя труд их волонтеров для развоза пищи, начали готовить прасад для этих детей.

Мы готовили и расфасовывали пищу, а волонтеры забирали у нас коробки с едой и развозили их по адресам. Но через некоторое время списки предоставленные КДН районов города закончились, а потом и пандемия сошла на «нет», и интерес к этой деятельности пропал. Но у нас интерес не пропал, и мы решили сосредоточить свою помощь на многодетных семьях.

В Нижнем Новгороде 8 районов и в каждом из них есть своё отделение ассоциации многодетных семей. В каждом районе от 1500 до 2000 тысяч таких семей. Это безбрежное море для деятельности, потому что за один раз мы кормим около 20

семей. Работы по кормлению таких детей хватит до конца жизни. Но, хочу сказать, что это самая благодарная публика – дети и многодетные матери.

Доброжелательность, чистота пищи и любовь, которую мы вкладываем в этот процесс – всё это ощутимо для них. У нас есть свой сайт, на котором можно увидеть тысячи фотографий улыбающихся детей и благодарных отзывов их родителей. Мы каждую неделю выкладываем на сайт фотоотчёт о нашей деятельности.

Бывало такое, что некоторые матери наших подопечных говорили моим мужьям: «Пойди и помоги им», и они приходили и помогали нам, кто чем мог, эти люди, совершенно не имеющие отношения к Сознанию Кришны.

- Сколько людей сейчас задействовано в проекте «Пища жизни» Харе Кришна Нижний Новгород на постоянной основе?

- Это примерно человек двадцать, но эта цифра постоянно меняется.

- Процесс приготовления пищи требует определенных знаний. Среди вас есть квалифицированные повара?

- Здесь раньше был один преданный, который сейчас уехал в Индию. Именно он обучал нас всему постепенно. Рацион мы готовим примерно одинаковый, только с незначительными изменениями. Меню мы составляем исходя из пожеланий родителей детей, которых мы кормим. И наша деятельность находит положительный, живой отклик у людей. Когда мы не работали какое-то время в связи с переездом, люди звонили нам и спрашивали, когда мы снова начнем кормить детей. Это означает, что есть такой социальный запрос.

- Как сейчас этот процесс выглядит технически?

- Мы сотрудничаем с областной ассоциацией многодетных семей. У них, в каждом районе есть свои ответственные лица. Потенциальных получателей наших посылок обзванивают и спрашивают, нужно ли им это, хотят ли они получить такую помощь. И если они говорят, что хотят, только после этого их включают в списки, которые затем передают нам. Это делается для того, чтобы эта помощь приходила туда, где это действительно нужно.

Мы готовим еду и фасуем ее по коробкам. Затем представители ассоциации забирают у нас эти коробки и уже сами доставляют их в семьи. На каждой коробке указывается фамилия получателя, и количество порций по количеству детей в этой конкретной семье.

Так как ресурс у нас не безграничный, мы говорим представителям ассоциации, какой объём работы мы готовы выполнить, и в соответствии с этим они дают нам списки потенциальных получателей помощи

Сейчас мы готовим комфортное для нас количество прасада, и это приносит радость как детям, так и нам.

- Если движение «Пища жизни» пошло от Шрилы Прабхупады, и действует сейчас по всему миру, как с этим обстоят дела в Индии?

Там это целая культура. В Индии, каждый имеющий такую возможность человек обязан кормить бедных. Очень часто индийцы ходят семьями в храм, и конечно же там дают пожертвования, они почитают старших и святых людей. В Индии давать пожертвования для тех, кто имеет такую возможность, это само собой разумеется. Каждый богатый индиец обязан сделать школу и ночлежку для бедных, устраивать бесплатные раздачи пищи.

- Есть ли у вас такое, что в проекте «Пища жизни» задействованы целые семьи?

- К нам приходят самые разные люди, в среднем в одной программе участвует около десяти человек. Занятость на одну программу – два дня в неделю – суббота и пятница. У людей есть желание помочь, и они реализуют его через такой способ служения. Это благое дело и к нам приходят как православные, шиваиты, так и те, кто не относит себя ни к какой конфессии.

Конечно есть те, кто приходят к нам целыми семьями, участвуют в наших программах и готовят прасад для детей.

Иван прабху – моряк дальнего плавания в мире, и он также с удовольствием выполняет служение в проекте «Пища жизни» вместе со своей супругой.

- Иван, Вы вместе с супругой участвуете в проекте «Пища жизни»?

- Сейчас участвую больше я, чем супруга. Она дома, с маленьким ребенком. Но по мере возможности жена готовит дома, а потом я привожу всё это сюда. Я научился от супруги готовить некоторые блюда, и теперь тоже готовлю сам.

- Расскажите немного о себе: как давно Вы и Ваша супруга в Сознании Кришны? Как пришли к тому, что стали участвовать в этом проекте?

- С преданными я знаком чуть больше десяти лет. В проекте участвую около четырех лет. На самом деле мы делаем здесь ни так много. Сейчас много волонтерских движений, которые более серьезно заняты подобной деятельностью. Мы задействованы здесь два дня в неделю по несколько часов. Полноценной загруженности нет, потому что люди ходят на работу и для нас это не является основным видом деятельности.

О проекте «Пища жизни» известно давно. И когда я узнал, что есть возможность присоединиться – я сделал это. Познакомившись с преданными можно научиться действовать бескорыстно. Здесь мы можем этому научиться, потому что за это мы не получаем ни какой оплаты. Но при этом мы получаем большое

внутреннее удовлетворение.

Мне всегда очень хочется приехать сюда. И я даже переживаю за то, что когда я приеду, для меня здесь не найдется работы.

- Чем Вы занимаетесь в жизни?

- Я – моряк дальнего плавания, и мне на долго приходится уходить в море. Я – мирской человек, но изучаю Священные писания и стараюсь заниматься духовной практикой под руководством старших преданных.

- Вы выполняете какие-то постоянные функции в этом проекте, или ту работу, какая есть на конкретный момент?

- И то и другое. Потому что большинство людей находятся здесь постоянно, а я уезжаю на 3-4 месяца и многое здесь происходит без меня, когда я приезжаю, то спрашиваю, какой работой мне заняться, и делаю это. Сейчас мы с супругой взяли на себя изготовление манников дома. Я спросил у старшего преданного, и он сказал, что было бы хорошо, если бы мы делали такие пироги, мы с женой теперь делаем их дома. Здесь делаю то служение, которое поручит старший.

- Как занятость в проекте «Пища жизни» сочетается с мирской деятельностью и духовной практикой?

- Это и есть преданное служение, часть духовной практики. Здесь есть алтарь, и мы просим у Господа разрешения послужить ему таким образом. Есть индивидуальная духовная практика: чтение Священных писаний, воспевание святого имени, а здесь у нас коллективная духовная практика. Пища, которую мы здесь готовим вегетарианская, также после приготовления мы освящаем её на алтаре, и таким образом она является прасадом. С мирской деятельностью это сочетается нормально. Мы задействованы здесь по 3-4 часа дважды в неделю. Всё это можно органично встроить в свой распорядок. У каждого из нас есть мирская деятельность: кто-то работает, кто-то учится и всё это органично сочетается с преданным служением и занятостью здесь.

- Какое чувство вызывает причастность к такой большой и благородной миссии, как распространение прасада?

Это чувство сопричастности к чему-то возвышенному. У каждого человека должна быть миссия: человек не

может жить просто так, удовлетворяя свои первичные потребности. И даже если кто-то занимается творчеством, то земной путь человека в любом случае заканчивается одним и тем же. Но когда человек участвует в какой-то миссии, он чувствует себя сопричастным к этому, при чём миссия эта достаточно возвышенная. И таким образом, человек чувствует себя счастливым.



Семейные ценности в Православии



Сизов Лев Алексеевич, аспирант
Казанский (Приволжский) федеральный университет

2024 год Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина объявлен Годом семьи. Без семьи не может существовать наше общество. Семейные ценности есть в каждой культурной и религиозной традиции. Поскольку культурная идентичность русского человека неразрывно связана с Православием, то стоит сказать, как Русская Православная Церковь, отдельные священники осмысливают семью.

Для начала определим, что такое христианский брак. На этот вопрос даёт хороший ответ известный священник Павел Островский. Он отмечает, что главная цель жизни – попасть Царство Небесное. И если брак ей соответствует, то его смело можно назвать христианским.

Брак – это союз между мужчиной и женщиной. Крайне важно единомыслие супругов (одна вера, схожий взгляд на фундаментальные вопросы), венчание, в котором они просят благословение Бога на брак, впускают его в свою жизнь. При этом Церковь уважительно относится к браку, зарегистрированному в ЗАГСе, но не признаёт неофициальный, т.н. «гражданский брак», и тем более однополые отношения.

Путь семьи очень ценится в Православии, но не является строго обязательным. Есть и путь монашества, к которому призывал апостол Павел, но с уважением относился к браку. Жить одному тоже не запрещается, лишь бы человек не впадал в блудные отношения. Здесь стоит пояснить: Церковь строго запрещает интимные отношения до брака (блуд). Если хочется интимных отношений, то нужно жениться/выйти замуж. Нельзя иметь интимные отношения вне брака. Однако другой известный священник Владислав Береговой отмечает, что холостяцкая жизнь плохо способствует нравственному совершенству. Легко считать себя хорошим человеком, не терпя недостатки других.

Говоря о иерархии в православной семье, важно процитировать апостола Павла: Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава

жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем (Еф. 5: 22–24). Есть распространённое мнение, что раз муж глава семьи, то жена должна его беспрекословно слушаться. Но это совсем не так. Для мужчин здесь ставится очень высокая планка. Муж должен брать пример с Христа, уподобляться ему, и тогда жена потянется за мужем. Дети являются плодом любви между супругами, хоть и не главной целью брака. Соответственно, по иерархии они занимают место после супругов. Подытоживая, уместно привести аналогию семьи с костром, выдвинутую отцом Павлом Островским «Семья — это костер, где у каждого свои функции: муж разжигает костер, жена поддерживает, а дети весело искрят».

Церковь с уважением относится к многодетности и сожалеет, когда супруги сознательно отказываются от рождения детей. Любое предохранение – грех и нарушение заповеди Божией «Плодитесь и размножайтесь». Церковь не наказывает за это, хотя и отмечает, что такое восприятие неверно. Но контрацепция разрешена, только если носит необортный характер.

Церковь с сожалением смотрит на участвующую практику разводов в обществе и считает их грехом. «Церковного» же развода как такого не существует. С точки зрения Церкви в определенных ситуациях брак может быть признан недействительным или утратившим каноническую силу. И такие обстоятельства очень ограничены, главное из которых – прелюбодеяние (измена). Подробнее об этом и не только можно почитать в документе «О канонических аспектах церковного брака», принятом на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 29 ноября — 2 декабря 2017 года. Важно понимать, что в таких случаях просьба рассмотреть вопрос о признании ее церковного брака утратившим каноническую силу – право, а не обязанность. Более того, «священнослужителям вменяется в обязанность всячески увещевать лиц, ищущих

развода, не принимать поспешных решений, но, по возможности, примириться и сохранить свой брак».

Воспитанию детей Церковь отводит очень большую роль. Как Господь Бог проявляет снисхождение и долготерпение к нам, так и мы должны поступать по отношению к своим детям. Отец Павел Островский пишет, что «Главная задача родителей в воспитании своих детей — это научить их послушанию». А для этого слова родителей не должны расходиться с делом. Если пообещал наказать за проступок – нужно это сделать. Но наказание должно быть пропорционально проступку. И ребёнок должен понимать, что это ему урок, а не срыв злости родителя на него. Важно отметить, что физические наказания и рукоприкладство строго запрещены. Необходимо иметь доверие, авторитет, личный пример в глазах детей. Детям крайне важно почитать своих родителей, так как есть 5 заповедей: Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Исх. 20, 12. Но это не значит, что ребёнок, будучи взрослым, должен их слушаться. Нужно как минимум иметь уважение к родителям, молиться за них, оказывать необходимый уход. Но при этом есть слова апостола Павла: «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали» (Кол.3:12). Отец Павел Островский приводит три примера такого раздражения: постоянное нравоучение, оскорбления, лицемерие. Что касается духовного воспитания, то в первую очередь дети должны видеть пример родителей. Если родители искренне живут духовной жизнью, то дети потянутся.

Таким образом, семейные ценности в Православии не просто дань культурной традиции, а неотъемлемая часть религиозной жизни. Безусловно, каждая семья сталкивается в жизни с разными трудностями, но с Богом нет ничего невозможного. И очень важно семейные ценности сохранить и преумножить.

Список использованных источников и литературы:

О канонических аспектах церковного брака [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: // <http://www.patriarchia.ru/db/text/5075384> (дата обращения: 24.09.2024).

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: // <https://predanie.ru/book/69763-osnovy-socialnoy-konceptcii-russkoy-pravoslavnoy-cerkvi/> (дата обращения: 24.09.2024).

Островский Павел, священник. О христианской семье. Любовь, подвиг и юмор. – М.: Нукая, 2023. – 272 с.

Семья, дети, работа. Строим жизнь по-христиански / священник Владислав Береговой. – Москва : Эксмо, 2023. – 256 с. – (Священники-блогеры: о любви, семье и вере).



Уфтыужская роспись उफ्तुझस्काया पेंटिंग



Путешествующие по Индии россияне всегда отмечают необыкновенное разнообразие народных ремесел: вышивка, резьба, роспись по дереву. Сегодня же мы хотим познакомить наших читателей с богатством народных ремесел Российской Федерации на примере уфтыужской росписи.

Уфтыужская роспись получила название по селу Верхняя Уфтыуга (сейчас Архангельская область), в окрестностях которой мастера изготавливали и расписывали дивными цветами берестяные изделия.

Точное время возникновения уфтыужского промысла неизвестно, но уже в 80-е – 90-е годы XIX века расписные берестяные туеса охотно раскупались на рынках Сольвычегодска, Великого Устюга, Архангельска и даже Москвы.

Основу промысла составляли расписные изделия из бересты – туеса, лукошки. Прялки расписывали только на заказ или на подарок; уфтыужский прялочный канон не успел сложиться и прялки этого центра являются большой редкостью.

Главный предмет уфтыужской росписи – берестяной туес-сколотень. Сработанные по особой технологии, такие туеса обладали герметичными свойствами и были незаменимыми предметами в крестьянском быту. В них хранили сыпучие продукты, муку, а также жидкости – молоко и воду, в больших туесах солили грибы. А расписанные яркими красками туеса

украшали дом, поэтому их охотно покупали.

Основной сюжет уфтыужской туесной росписи: изящно изогнутая веточка-Древо и стоящая рядом птичка, «Кутенька» – так мастера ласково называли изображаемых птиц.

Роспись знаменита орнаментальным мотивом – тюльпаном. Тюльпаны присутствуют во многих росписях, но именно в уфтыужской они заняли главное место и являются визитной карточкой росписи. Мастера называли тюльпаны «котлами» из-за характерной формы, похожей на котел.

Мотив тюльпана, напоминающий древнегреческий крин-лилию, широко распространен в декоративно-прикладном искусстве Русского Севера. Тюльпаны, мы встречаем повсеместно: в росписи по дереву, в вышивках головных женских уборов, скани, эмалях, изразцах. «Крин» – лилия в переводе с греческого. Крины пришли к нам из Византии и заняли прочное место в древнерусском орнаментальном декоре.

Уфтыужская роспись в основном выполнялась на красных, красно-коричневых, оранжевых фонах. Часто для фона использовался свинцовый сурик, дающий красивый теплый оранжевый цвет. Иногда использовали белые, желтые и даже зеленые «земли». Сухие пигменты мастера растирали и смешивали с мучным или столярным клеем, краски получались прочные: старинные

туеса поражают сохранность красочного слоя.

Уфтыужская роспись запоминается легкостью и изяществом письма, свободным размещением изобразительного мотива. «Каждый штрих и мазок поражают точностью, убедительностью и изяществом» пишет исследователь росписи В. М. Вишневская и дает емкую характеристику росписи – «кистевая каллиграфия».

К середине XX века промысел практически исчез, остались несколько мастеров, которым некому было передавать ремесло.

В настоящее время интерес к традиционной росписи растет, и уфтыужский промысел ждет возрождение. Уфтыужская роспись обладает огромным запасом композиционных, графических и колористических приемов. Сочетание полновесных кистевых элементов, тончайших линий, изящной каллиграфии делает уфтыужскую роспись созвучной нашему времени.



Художница Светлана Зеленцова



СТИХИ...



Слепова Ольга Викторовна

Член Российского союза писателей,
лауреат Национальной литературной премии «Золотое перо Руси» в номинации «Моя малая Родина».
Автор 10 поэтических книг, в том числе двух – для детей.
Один из детских сборников стихов «Свет радости» издан на двух языках – русском и хинди

Звёздная Семья Рерихов

Среди семейных человеческих букетов
Есть русская Семья из солнечных цветов.
Она планете подарила столько Света,
Что хватит для цветенья будущих садов:

Семья художников, философов, учёных,
Защитников святынь народных, Красоты,
Идеями о мире в жизни окрылённых,
Трудившихся для претворения мечты!

Для Рерихов весь мир был полем созиданья,
А Индия, как и Россия, – отчий дом!
Здесь, в этих странах, их великие деянья,
Здесь сердце наполнилось космическим огнём!

В России, в Индии воспеты древность, храмы,
Герои и Подвижники, Учителя,
И Гималаи с серебристыми снегами,
И дружественных стран священная земля.

Отсюда мысль об охраненье всей Культуры
Стрелой летела к людям, к действиям звала.
В Нагаре Рерих почитался мудрым Гуру.
Здесь в институте мощь наука обрела.

Велики Рерихи! Букет их – гармоничный.
Из четверых в нём каждый – солнечный цветок.
В своём немеркнущем сиянье безграничном
Они объединились в пламенный поток



У скамьи в усадьбе Рерихов

Наггар. Усадьба Рерихов. Скамья.
Здесь отдыхала вечером Семья.
Играл и пел домашний патефон,
В Их путешествиях был другом он.
Любимые пластинки берегли.
Их песни в праведном пути вели.

Мелодия звучала из окна,
К берёзам уносила мысль она,
И к городу-музею на Неве,
И к колокольным звонам в синеве...

Напевный ритм сменял аккорд огней:
Торжествовал в пространстве Прометей!
И снова музыка лилась рекой –
О Будущем прекрасною мечтой.

И ввысь летел ладов её каскад,
И устремлялся дух в безбрежный сад,
К сиянию звёздных россыпей-цветов,
К далёким сферам неземных миров.

Через искусство, через звук и цвет,
В сердца божественный струился Свет.
Созвучьям из открытого окна
Внимала молча горная страна.

Рахманинов и Скрябин, Вагнер, Бах...
Гармония, молитва в их трудах!
Бетховен, Римский-Корсаков, Шопен...
Для Рерихов ритм музыки священ!

Сегодня только липа над скамьёй
Мелодий ждёт вечернею зарёй...

**В 2024 году отмечают юбилей
членов великой семьи Рерихов:
150 лет со дня рождения Н.К. Рериха,
145 лет со дня рождения Е.И. Рерих и
120 лет со дня рождения С.Н. Рериха.
Гармония, духовное и творческое единство
царили в семье.
Семья Рерихов – это пример семьи будущего.**

रूसी-भारतीय मैत्री संघ 'दिशा' द्वारा हिंदी दिवस पर सम्मानित हिंदी विद्वानों का विवरण



सुश्री ल्युदमीला खखलोवा

सन : 2015

संस्थान : अफ्रीकन एशिया मास्को स्टेट विश्वविद्यालय

सम्मान : हिन्दी मित्र सम्मान

क्षेत्र : हिन्दी अध्यापन



सुश्री एकतेरीना कोस्तिना

सन : 2018

संस्थान : सेंटपिटर्स राजकीय विश्वविद्यालय

सम्मान : पद्मश्री मदन लाल मधु-‘हिंदी सेवा सम्मान’

क्षेत्र : हिंदी प्रचार एवं शिक्षण



सुश्री येकतिरीना पानिना

सन : 2016

संस्थान : अफ्रीकन एशिया मास्को स्टेट विश्वविद्यालय

सम्मान : हिन्दी मित्र सम्मान

क्षेत्र : हिन्दी शिक्षण



श्री सागर सूद

सन : 2018

संस्थान : साहित्य कलश प्रकाशन

सम्मान : पद्मश्री मदन लाल मधु-‘हिंदी सेवा सम्मान’

क्षेत्र : हिंदी साहित्यकार एवं संपादक



श्रीमती इंदिरा गाजिएवा

सन : 2017

संस्थान : रूसी राजकीय मानविकी विश्वविद्यालय मास्को

सम्मान : पद्मभूषण अल्कजांद्र कदाकिन ‘हिंदी मित्र सम्मान’

क्षेत्र : हिंदी के प्रचार प्रसार एवं शिक्षण



डॉ. अलेक्सांद्र सेंकेविच

सन : 2019

संस्थान : साहित्य, सांस्कृतिक और व्यावसायिक

सम्मान : पद्मश्री मदन लाल मधु-‘हिंदी सेवा सम्मान’

क्षेत्र : कवि, कथाकार, साहित्यिक अनुवादक और भारतविज्ञ



श्री दिमित्री बाब्काव

सन : 2017

संस्थान : कजान फेडरेशन युनिवर्सिटी

सम्मान : पद्मश्री मदन लाल मधु-‘हिंदी सेवा सम्मान’

क्षेत्र : हिंदी अनुवाद एवं शिक्षण



डॉ. क्लारा दुकोवा

सन : 2019

संस्थान : मास्को अंतर्राष्ट्रीय संस्थान

सम्मान : पद्मभूषण अल्कजांद्र कदाकिन ‘हिंदी मित्र सम्मान’

क्षेत्र : हिन्दी शिक्षण



श्रीमती ग्युजेल स्त्रेलकोवा

सन : 2018

संस्थान : अफ्रीकन एशिया मास्को स्टेट विश्वविद्यालय

सम्मान : पद्मभूषण अल्कजांद्र कदाकिन ‘हिंदी मित्र सम्मान’

क्षेत्र : हिंदी शिक्षण एवं विकास हेतु



श्री सुशील कुमार ‘आज़ाद’

सन : 2019

संस्थान : प्राध्यापक केंद्रीय विद्यालय मास्को

सम्मान : पद्मभूषण अल्कजांद्र कदाकिन ‘हिंदी मित्र सम्मान’

क्षेत्र : हिंदी के प्रचार प्रसार

इंडियन अवार्ड / RUSSIAN NATIONALS RECIPIENT OF PADMA AWARDS

PADMA BHUSHAN



1961	Svetoslav Roerich (1904-1993)	Arts
2002	Evgeny Chelyshev (1921-2020)	Literature & Education
2002	Gury Marchuk (1925-2013)	Science & Engineering
2003	Herbert Yefremov (1933-)	Science & Engineering
2006	Grigory Bongard-Levin (1933-2008)	Literature & Education
2008	Yuli Vorontsov (1929-2007)	Public Affairs
2018	Alexander Kadakin (1946-2017)	Public Affairs

PADMA SHRI



1991	Madan Lal Madhu (1925-2014)	Literature & Education
2000	Grigoriy Bondarevsky (1920-2003)	Literature & Education
2004	Tatyana Elizarenkova (1929-2007)	Literature & Education
2007	Rostislav Rybakov (1938-2019)	Literature & Education
2007	Miriam Salganik (1930-2019)	Literature & Education
2008	Gennady Pechnikov (1926-2018)	Arts
2022	Tatyana Shaumyan (1938-)	Literature & Education

DIPOSAV-2018

U.P. APRAWASI BHARTIYA RATAN AWARD -2019



Rameshwar Singh (1961-)

Cultural & Welfare

ПАРТНЕРЫ:



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:



NEWS portal
НОВОСТНОЙ портал



WE HELP YOU TO FULFIL YOUR ACADEMIC DREAMS!



STUDY IN RUSSIA




**Largest Overseas
Education Provider**

Rus Education is one of the largest overseas medical education providers for Indian Students.



**Representative
Offices**

Rus Education has Indian representatives in the universities to facilitate Indian Students in Russia.



**Privately Managed
Hostels**

Hostels and mess facilities are provided to Indian students at the Top Government Medical Universities in Russia.

Our Partner Universities



**PERM STATE
MEDICAL UNIVERSITY**

Established in 1916



MARI STATE UNIVERSITY

Established in 1972



**ORENBURG STATE
MEDICAL UNIVERSITY**

Established in 1944



**PSKOV STATE
UNIVERSITY**

Established in 2010



**TVER STATE
MEDICAL UNIVERSITY**

Established in 1936



HEAD OFFICE, DELHI

Russian House in New Delhi, 24, Firozeshah Road,
Vakil Lane, Mandi House, New Delhi, 110001
Web: www.ruseducation.in

Toll Free

1800-833-3338